RNI-UPHIN/2009/30721

दिल्ली
अधिकतम तापमान 30 डिग्री
न्युनतम तापमान 27 डिग्री

एनसीआर
अधिकतम तापमान 29 डिग्री
न्युनतम तापमान 26 डिग्री

गुरुवार 28 अगस्त 2025
सूर्योदय प्रातः 05:58 बजे
सूर्यास्त सांय 18:48 बजे

www.khabariya.com

एनसीआर टुडे

करंट न्यूज करंट व्यूज

पृष्ठ 4 आर्थिक ब्रह्मास्त्र है स्वदेशी

उत्तर प्रदेश और दिल्ली से एक साथ प्रकाशित | वर्षः 16 | अंकः 313 | गाजियाबाद, गुरुवार 28 अगस्त 2025 | मूल्यः ₹ 2 | पेजः 06 | विक्रमी संवत् 2081 | युगाब्द 5126 | शाक 1946

केनरा बैंक Canara Bank
SCAN & PAY
UPI ID: 300012627000246@cnrb
BHIM UPI
Canara ai1 | CBDC | Paytm
Cred | PhonePe | Google Pay
DIGITAL RUPEE ACCEPTED HERE

राष्ट्रपति, पीएम समेत नेताओं ने देशवासियों को दी गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं

✷ एनसीआर टुडे. नई दिल्ली ✷। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को देशवासियों को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। पोस्ट में उन्होंने लिखा, "देश-विदेश में रह रहे सभी भारतीयों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं! यह महापर्व बुद्धि और विवेक के देवता भगवान श्री गणेश के जन्मोत्सव के रूप में हर्षोल्लास से मनाया जाता है। विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश से मैं प्रार्थना करती हूं कि वे व्यक्ति-निर्माण तथा राष्ट्र-निर्माण के मार्ग की सभी बाधाओं को दूर करते रहें तथा उनके आशीर्वाद से सभी देशवासी, पर्यावरण-अनुकूल जीवन शैली अपनाते हुए, सशक्त भारत के निर्माण में निष्ठा के साथ कार्यरत रहें। गणपति बाप्पा मोरया।"

बाढ़ से जम्मू मंडल में 104 ट्रेनों का संचालन प्रभावित

✷ एनसीआर टुडे. नई दिल्ली ✷। जम्मू-कश्मीर के चक्की नदी में भारी कटाव और अचानक आई बाढ़ के कारण जम्मू मंडल में रेल यातायात अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है। इस वजह से 104 ट्रेनों का संचालन प्रभावित हुआ है। उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बुधवार को बताया कि इस स्थिति के चलते कुल 44 ट्रेनों को रद्द करना पड़ा है। इसके अलावा 16 ट्रेनों की शुरूआत को छोटे स्टेशनों से किया गया है और 28 ट्रेनों को गंतव्य तक पहुंचने से पहले ही समाप्त करना पड़ा है। छह ट्रेनों का आंशिक रूप से संचालन बहाल कर दिया गया है, जबकि सात ट्रेनों का पूर्ण रूप से परिचालन बहाल हो गया है। इसी तरह तीन ट्रेनों को वैकल्पिक मार्ग से संचालित किया जा रहा है। रेल प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा पर निकलने से पहले ट्रेनों की स्थिति की जानकारी प्राप्त कर लें।

गाजा में पत्रकारों की हत्या स्तब्धकारी और अत्यंत खेदजनक: भारत

✷ एनसीआर टुडे. नई दिल्ली ✷। भारत ने इजरायल और हमास के बीच चल रहे संघर्ष के दौरान गाजा पट्टी पर हमले में पत्रकारों की मौत की निंदा करते हुए इसे अफसोस जनक करार दिया है। विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने गाजा पट्टी के खान यूनिस में हमलों में पत्रकारों की मौत के संबंध में मीडिया के प्रश्नों के जवाब में बुधवार को कहा कि भारत ने संघर्षों के दौरान आम नागरिकों के मारे जाने की हमेशा निंदा की है। उन्होंने कहा , "पत्रकारों की हत्या श्तब्धकारी और अत्यंत खेदजनक है। भारत ने हमेशा संघर्ष में नागरिकों की जान जाने की निंदा की है। हम समझते हैं कि इज़रायली अधिकारियों ने पहले ही जाँच शुरू कर दी है।' उल्लेखनीय है कि सोमवार को गाजा पट्टी पर इजरायली हमले में पांच पत्रकारों की मौत हुई है। इसे लेकर इजरायली सेनाओं की दुनिया भर में आलोचना हो रही है।

'मोदी मित्र' के टैरिफ से कई क्षेत्रों में होगा भारी नुकसान, लाखों नौकरियों पर खतरा : खरगे

✷ एनसीआर टुडे. नई दिल्ली ✷। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ व्यापारिक रिश्तों को लेकर तीखा हमला बोला है। खरगे ने आरोप लगाया कि मोदी की विदेश नीति की नाकामी के कारण आज भारत को गंभीर आर्थिक झटका लग रहा है। उन्होंने कहा कि ट्रंप सरकार ने भारत पर 50 प्रतिशत आयात शुल्क लागू कर दिया है, जिससे अकेले दस प्रमुख क्षेत्रों में 2.17 लाख करोड़ रुपये का नुकसान होने का अनुमान है।

शोध का वास्तविक समाज और जनता तक पहुंचाना बहुत जरूरी: आनंदीबेन पटेल

✷ वेबवार्ता. झांसी ✷

उत्तर प्रदेश की राज्यपाल और झांसी स्थित बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने कहा है कि विश्वविद्यालय में होने वाले शोध का वाश्तविक लाभ समाज और जनता तक पहुंचाना बहुत जरूरी है।

उन्होंने बुधवार को विश्वविद्यालय के 30 वें दीक्षांत समारोह में अपने संबोधन में कहा कि शोध कर फाइलों में बंद कर देना पर्याप्त नहीं बल्कि उसके आधार पर सुधारात्मक निर्णय होने चाहिए। शोध के परिणाम का यदि सही उपयोग न हो तो वह केवल दश्तावेज बनकर रह जाता है। उन्होंने रिसर्च प्रोजेक्ट्स में फंडिंग एजेंसियों की पारदर्शिता पर सवाल उठाये और उनके द्वारा की जाने वाली अनियमितताओं की समीक्षा की जरूरत को रेखांकित किया। राज्यपाल ने छात्रों को शिक्षा के अभिन्न अंग के रूप में शोध कार्य और अनुशासन के महत्व को समझाया।

श्रीमती पटेल ने कक्षाओं में छात्रों की उपस्थिति को लेकर चिंता जताते हुए परीक्षा में बैठने के लिए कम से कम 75 प्रतिशत उपस्थिति को अनिवार्य बताया। इसके साथ ही शिक्षकों की उपस्थिति और समय पालन पर भी टिप्पणी करते हुए राज्यपाल ने शिक्षकों की जिम्मेदारी और निगरानी की जरूरत का उल्लेख भी किया। आज प्रदत्त कुल उपाधियों और पदकों में क्रमशः 58. 32 प्रतिशत तथा 73.52 प्रतिशत के साथ छात्राओं ने अपना दबदबा बनाया जबकि इसकी तुलना में छात्रों की हिस्सेदारी 41. 67 प्रतिशत तथा 26. 47 प्रतिशत रही।

विश्वविद्यालय परिसर के गांधी सभागार में आयोजित इस समारोह में मुख्य अतिथि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ-उत्पादन समन्वय और सेवा इंटरैक्शन) महानिदेशक डॉ चंद्रिका कौशिक, विशिष्ट अतिथि उच्च शिक्षा राज्यमंत्री रजनी तिवारी और कुलपति प्रो. मुकेश पाण्डेय भी उपस्थिति रहे। डॉ चंद्रिका कौशिक ने विश्वविद्यालय के नैक ए प्लस प्लस और एनआईआरएफ रैंकिंग सहित अन्य उपलब्धियों पर बधाई देते हुए कहा कि युवा पीढ़ी ही तकनीकी बदलाव और शोध की रीढ़ है। छात्र नयी तकनीकों पर काम करके देश को आत्मनिर्भर और दुनिया में अग्रणी बनाने में भूमिका निभाएं। उच्च शिक्षा राज्यमंत्री रजनी तिवारी ने उपाधि और पदक प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं,अभिभावकों और गुरूजनों को बधाई देते हुए कहा कि पदक एवं उपाधि हासिल करने में छात्रों के दबदबे से समाज में एक बेहद सकारात्मक बदलाव आ रहा है। उन्होंने कहा कि दीक्षांत समारोह जीवन का एक नया अध्याय शुरू करने का अवसर है। यह आपके परिश्रम, लक्ष्य और संकल्प से तय होगा कि आप समाज, प्रदेश और देश को किस प्रकार आगे बढाते हैं1

इस अवसर पर विश्वविद्यालय द्वारा 50 वर्ष पूर्ण होने पर स्वर्णायनम पत्रिका, दीक्षांत पत्रिका, स्वर्णप्रज्ञानंम, चितरी, संचारिका, एक प्रगति आख्या स्टार्टअप विवरण का उन्नत भारत अभियान, टीवी पेशेंट कार्यक्रम, देवी अहिल्याबाई प्रतियोगिता पत्रिका के साथ ही छात्र ऋतिक पटेल द्वारा कुलाधिपति के वचनों की संकलित पत्रिका संकल्प का विमोचन किया गया।

कुलाधिपति द्वारा देवी अहिल्याबाई महिला छात्रावास, कारगुआ जी स्थित कृषि फार्म के दो कक्ष एवं रेस्ट रूम , अर्थशास्त्र एवं वित्त संस्थान के छह कक्षों , शिक्षा संस्थान भवन के चार कक्षों, कंप्यूटर सेंटर भवन , उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्राप्त अनुदान से आच्छादित फार्मेसी संस्थान भवन के दो कक्षों एवं सेमिनार हॉल , उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्राप्त अनुदान से आच्छादित कृषि विज्ञान संस्थान भवन के छह कक्षों एवं कॉन्फ्रेंस हॉल एवं उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अनुदान से आच्छादित आउटडोर स्टेडियम की आरसीसी वॉल का लोकार्पण किया गया। श्रीमती पटेल ने उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्राप्त अनुदान से आच्छादित कर्मचारी आवासों के निर्माण कार्य, कृषि विज्ञान संस्थान भवन की कक्षाओं एवं प्रयोगशालाओं के उच्चीकरण कार्य, आवासीय परिसर की बाउंड्री वॉल की मरम्मत के कार्य, आउटडोर स्टेडियम में टेनिस कोर्ट एवं हाई मास्क लाइट के कार्य का शिलान्यास भी किया।

अनाम पार्टियों को मिले चंदे पर राहुल ने चुनाव आयोग पर साधा निशाना

✷ एनसीआर टुडे. नई दिल्ली ✷

चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाने के कारण उनसे एफिडेविट की मांग से घिरे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आयोग को बुधवार कटघरे में खड़ा करते हुए सवाल किया है कि गुजरात अनाम पार्टियों ने हज़ारों करोड रुपए का चंदा जुटाया है तो क्या उनसे भी शपथ पत्र मांगा जाएगा। श्री गांधी ने कहा कि जिन पार्टियों को भारी रकम चंदे के रूप में मिली है उनको कोई जानता नहीं है और न ही उन्होंने ज्यादा चुनाव लड़े हैं। इन पार्टियों को जितना चंदा मिला है उसका कहीं कोई हिसाब किताब नहीं है।

उन्होंने कहा कि इन दलों से भी चुनाव आयोग को शपथ पत्र मांगना चाहिए। उन्होंने कहा 'गुजरात में कुछ ऐसी अनाम पार्टियां हैं जिनका नाम किसी ने नहीं सुना-लेकिन 4300 करोड़ का चंदा मिला। इन पार्टियों ने बहुत ही कम मौकों पर चुनाव लड़ा है, या उन पर खर्च किया है।'

कांग्रेस नेता ने सवाल किया कि इन अनाम पार्टियों के खातों में ये हजारों करोड़ रुपये आए कहां से, इन पार्टियों को चला कौन रहा है और चंदे का जो पैसा इन पार्टियों की खाते में गया वह पैसा कहां है। उन्होंने चुनाव आयोग से सवाल किया, "क्या चुनाव आयोग जांच करेगा - या फिर यहां भी पहले एफिडेविट मांगेगा या फिर कानून ही बदल देगा, ताकि ये डेटा भी छिपाया जा सके।"

खराब मौसम के कारण लेह एयरपोर्ट का रनवे बंद एयर इंडिया की उड़ानें रद्द

✷ एनसीआर टुडे. नई दिल्ली ✷

जम्मू-कश्मीर में लगातार हो रही बारिश के कारण नदियों का जलश्तर बढ़ गया है, जिससे जम्मू क्षेत्र के कुछ हिस्सों में बाढ़ आ गई है।

लेह में खराब मौसम के कारण रनवे और कई टैक्सीवे पर कीचड़ जमा होने से उड़ानें निलंबित कर दी गई है। दिल्ली एयरपोर्ट ने यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की है।

एयर इंडिया ने बुधवार को प्रतिकूल मौसम की स्थिति के कारण यात्रियों के लिए एक यात्रा सलाह जारी की है। एयरलाइंस ने कहा है कि खराब मौसम के कारण लेह एयरपोर्ट का रनवे फिलहाल बंद है, जिससे उड़ानों का संचालन प्रभावित हो रहा है। इसके फलस्वरूप 27 अगश्त को लेह आने-जाने वाली हमारी निर्धारित उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। कंपनी ने कहा कि यदि आपकी बुकिंग इस व्यवधान से प्रभावित होती है, तो कृपया अपने ट्रैवल एजेंट से संपर्क करें या वैकल्पिक उड़ान विकल्पों पर विचार करने या पूर्ण धनवापसी के साथ अपनी बुकिंग रद्द करने के लिए 24x7 संपर्क केंद्र से संपर्क करें: +91 116 932 9333/+91 116 932 9999 आपके धैर्य और समझ के लिए धन्यवाद।

इससे पहले दिल्ली एयरपोर्ट ने भारी बारिश के कारण रनवे और कई टैक्सीवे पर कीचड़ जमा होने का हवाला देते हुए एक संशोधित नोटम जारी किया है। इसके बाद लेह के लिए उड़ानें 28 अगश्त की सुबह कम 7 बजे तक निलंबित रहेंगी। इस लंबी अवधि के बंद के साथ ही इस उच्च-ऊंचाई वाले एयरपोर्ट पर उड़ानों में व्यवधान का लगातार तीसरा दिन है।

कैबिनेट: पीएम स्वनिधि योजना की ऋण अवधि के पुनर्गठन और विस्तार को मंजूरी

✷ एनसीआर टुडे. लखनऊ ✷

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 'प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना' की ऋण अवधि के पुनर्गठन और विश्तार को मंजूरी दी है। ऋण अवधि अब पिछले वर्ष 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 मार्च 2030 कर दी गई है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना को आज मंजूरी दी। इस योजना का कुल परिव्यय 7,332 करोड़ रुपये है। पुनर्गठित योजना का लक्ष्य 50 लाख नए लाभार्थियों सहित 1.15 करोड़ लाभार्थियों तक लाभ पहुंचाना है। एक सरकारी बयान के अनुसार पुनर्गठित योजना की प्रमुख विशेषताओं में पहली और दूसरी किश्त में बढ़ी हुई ऋण राशि, दूसरा ऋण चुकाने वाले लाभार्थियों के लिए यूपीआई-लिंक्ड रुपे क्रेडिट कार्ड का प्रावधान और खुदरा एवं थोक लेनदेन के लिए डिजिटल कैशबैक प्रोत्साहन शामिल हैं।

इस योजना का दायरा वैधानिक शहरों से आगे बढ़कर जनगणना शहरों, अर्ध-शहरी क्षेत्रों आदि तक चरणबद्ध तरीके से बढ़ाया जा रहा है। उन्नत ऋण संरचना में पहली किश्त के ऋण को बढ़ाकर 15 हजार रुपये (10 हजार रुपये से) और दूसरी किश्त के ऋण को बढ़ाकर 25 हजार रुपये (20 हजार रुपये से) कर दिया गया है, जबकि तीसरी किश्त 50 हजार रुपये पर अपरिवर्तित रहेगी।

यूपीआई-लिंक्ड रुपे क्रेडिट कार्ड की शुरुआत से रेहड़ी-पटरी वालों को किसी भी आकस्मिक व्यावसायिक और व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तुरंत ऋण उपलब्ध होगा। इसके अलावा, डिजिटल अपनाने को बढ़ावा देने के लिए, रेहड़ी-पटरी वाले खुदरा और थोक लेनदेन पर 16 सौ रुपये तक के कैशबैक प्रोत्साहन का लाभ उठा सकते हैं।

यह योजना उद्यमिता, वित्तीय साक्षरता, डिजिटल कौशल और विपणन पर ध्यान केंद्रित करते हुए रेहड़ी-पटरी वालों की क्षमता निर्माण पर भी केंद्रित है। एफएसएसएआई के साथ साझेदारी में रेहड़ी-पटरी वालों के लिए मानक स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण आयोजित किए जाएंगे।

उल्लेखनीय है कि सरकार ने कोविड-19 महामारी के दौरान अभूतपूर्व कठिनाइयों का सामना करने वाले रेहड़ी-पटरी वालों की सहायता के लिए 1 जून 2020 को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना शुरू की थी। हालांकि, इस योजना की शुरुआत से ही यह रेहड़ी-पटरी वालों के लिए वित्तीय सहायता से कहीं बढ़कर साबित हुई है और इसने उन्हें अर्थव्यवस्था में उनके योगदान के लिए एक पहचान और औपचारिक मान्यता प्रदान की है।

स्टालिन बिहार की 'वोटर अधिकार यात्रा' में शामिल हुए

✷ वेबवार्ता. मुजफ्फरपुर ✷

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) की सांसद कनिमोई के साथ बिहार

के मुजफ्फरपुर जिले में कांग्रेस की 'वोटर अधिकार यात्रा' में बुधवार को शामिल हुए।

स्टालिन ने 'वोटर अधिकार यात्रा' में शामिल होने के तुरंत बाद सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर लिखा, ''बिहार पहुंच गया हूं...आदरणीय लालू प्रसाद जी की धरती अपनी आंखों में आग लेकर मेरा स्वागत करती है, इसकी मिट्टी पर हर चुराए गए वोट का बोझ है। मैं अपने भाइयों राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और बहन प्रियंका गांधी वाद्रा के साथ उस 'वोटर अधिकार यात्रा' में शामिल हुआ जो लोगों के दर्द को अजेय ताकत में बदल देती है।''

इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता तेजस्वी यादव ने 'वोटर अधिकार यात्रा' के दौरान बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की सड़कों पर बुधवार को मोटरसाइकिल चलाई। इस दौरान वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाद्रा को मोटरसाइकिल पर अपने भाई के पीछे बैठे देखा गया।

यात्रा के दरभंगा जिले से मुजफ्फरपुर पहुंचने पर राहुल गांधी एवं यादव मोटरसाइकिल चलाते नजर आए और इस दौरान लोग उनका स्वागत करने के लिए सड़कों के किनारे खड़े थे। कुल 1,300 किलोमीटर की यह यात्रा 17 अगश्त को सासाराम से शुरू हुई थी और एक सितंबर को पटना में एक रैली के साथ समाप्त होगी।

यूपी में बाढ़ से 22 जिलों में 2.52 लाख लोग प्रभावित

✷ एनसीआर टुडे. लखनऊ ✷

पहाड़ों और मैदानी इलाकों में लगातार बारिश के कारण उत्तर प्रदेश के 22 जिलों के 700 से ज़्यादा गांव जलमग्न हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को राहत कार्य में तेजी लाने, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और मवेशियों के लिए विशेष व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं।

मूसलाधार बारिश के कारण हिमालय से निकलने वाली नदियां और छोटी नदियां उफान पर आ गईं। बांधों और बैराजों को भारी मात्रा में पानी छोड़ना पड़ा जिससे निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति और बिगड़ गई।

राहत आयुक्त भानु चंद्र गोस्वामी ने बताया कि फिलहाल 22 जिलों की 43 तहसीलें और 768 गांव जलमग्न हैं। इससे 2.52 लाख लोग प्रभावित हैं।

उन्होंने बताया कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों को राहत सहायता प्रदान की गई है और 33,370 मवेशियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। उन्होंने बताया कि 550 नावों के माध्यम से इन प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री पहुंचाई जा रही हैं। कुल 278 बाढ़ आश्रय स्थल बनाए गए हैं, जिनमें 3,089 लोग रह रहे हैं। इन सभी की 586 टीमों द्वारा चिकित्सा जांच की जा रही है। इसके साथ ही, स्थिति पर नज़र रखने के लिए 1,022 बाढ़ चौकियाँ स्थापित की गई हैं।

बाढ़ से प्रभावित 22 जिलों में वाराणसी, प्रयागराज, औरैया, बहराइच, बांदा, मिर्जापुर, कानपुर देहात, चंदौली, फतेहपुर, कानपुर नगर, बाराबंकी, बदायूं, फर्रुखाबाद, गोंडा, हरदोई, कासगंज, लखीमपुर खीरी, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, शाहजहांपुर और उन्नाव शामिल हैं।

गौरतलब है कि उत्तर भारत के बड़े हिस्से में मंगलवार को लगातार बारिश हुई जिससे हिमालयी क्षेत्र में भारी तबाही मची। भूस्खलन निचले इलाकों में पानी भर जाने और कई सड़कें और पुल बह गए।

ओडिशा में महिला कर उपायुक्त रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार

✷ वेबवार्ता. भुवनेश्वर ✷

ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में तैनात जीएसटी उपायुक्त सरिता बारिक को एक बेकरी मालिक से टैक्स मामलों से संबंधित जुर्माने और छूट के बदले 25 हजार रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।

सतर्कता निदेशालय के अनुसार, सर्किल चार में तैनात प्रथम श्रेणी की अधिकारी सुश्री बारिक को कल यहां के मधुसूदन नगर में अपनी कार के अंदर रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। उनके कब्जे से पूरी रकम बरामद कर ली गयी है।

इस मामले में एक बेकरी चलाने वाले शिकायतकर्ता को नोटिस मिला था जिसमें वित्त वर्ष 2020-21 के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) संबंधित करीब सवा दो लाख रुपये के भुगतान के साथ-साथ जुर्माना और दंड भरने को कहा गया था। जब उन्होंने राहत की गुहार लगाई, तो सुश्री बारिक ने कथित तौर इस काम के लिए 25,000 रुपये की रिश्वत मांगी। बेकरी मालिक ने सतर्कता अधिकारियों से संपर्क किया तो अधिकारियों ने जाल बिछा कर सुश्री बारीक को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया

गिरफ्तारी के बाद, सतर्कता टीमों ने बारिक से जुड़ी तीन जगहों की एक साथ तलाशी ली। भुवनेश्वर स्थित उनके किराए के घर से 1.45 लाख रुपये नकद, 222 ग्राम सोना, गहनों के बिल, भुवनेश्वर में संपत्ति खरीद से संबंधित दश्तावेज और बैंक में जमा लगभग 60 लाख रुपये की राशि का पता चला। सतर्कता अधिकारियों ने बताया कि भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा 7 के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामले की जांच की जा रही है।

तमंचा कारतूस सहित अभियुक्त गिरफ्तार

✷ **एनसीआर टुडे. अलीगढ़** ✷। जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध शस्त्र रखने वाले शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु जनपद में चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना गंगीरी पुलिस टीम ने एक शातिर अभियुक्त पुष्पेन्द्र पुत्र नाथूराम निवासी कुंजलपुर थाना देहलीगेट जनपद अलीगढ़ को एक तमंचा 12 बोर व एक जिन्दा कारतूस 12 बोर के साथ शादीपुर वाली बम्बे की पुलिया के करीब बिजली के खम्भे के पास से गिरफ्तार किया।

सफ़ाई व्यवस्था में सुधार के लिए 16 नए ट्रैक्टरो को महापौर नगर आयुक्त ने किया रवाना

✷ **एनसीआर टुडे. अलीगढ़** ✷। बुधवार को महापौर प्रशांत सिंघल व नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने संयुक्त रूप से नगर निगम वर्कशॉप के लिए ख़रीदे गए 16 नग पॉवर ट्रैक 40 एचपी के ट्रैक्टरो को विधिवत पूजा अर्चना के साथ हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। नगर निगम ड्राइवर संघ के अध्यक्ष शेखर जीवन महामंत्री उदय सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों नगर निगम ड्राइवर्स ने महापौर व नगर आयुक्त का पगड़ी पहनाकर ट्रैक्टर मगाने पर आभार व्यक्त किया। नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने बताया कि शासन द्वारा अवमुक्त धनराशि से 15वे वित्त आयोग अंतर्गत नगर निगम द्वारा 16 नग पॉवर ट्रैक 40 एचपी के ट्रैक्टर मय ट्राली के क्रय किये गए है। इन 16 नग ट्रैक्टर मय ट्राली के आने से शहर की सफाई व्यवस्था में बड़ी राहत मिलेगी। इन 16 नए ट्रैक्टर के नगर निगम में आने से शहर की गलियों व सड़को से कचरा व सिल्ट उठाने की व्यवस्था प्रभावी बनेगी। नगर आयुक्त ने कहा नगर निगम शहर की सफाई व्यवस्था बेहतर बदलाव लाने के लिए प्रयासरत है आने वाले समय में सफाई व्यवस्था में सुधार के लिए कई आधुनिक साफ उपकरणों व संसाधनों को नगर निगम क्रय करेंगा।

महापौर व नगर आयुक्त ने मशीन का शुभारंभ कर चलवाई मशीन

✷ **एनसीआर टुडे. अलीगढ़** ✷। शहर की सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने की दिशा में नगर निगम ने एक और सराहनीय कदम उठाया है। लगभग 1 करोड़ 50 लाख रुपये की लागत से खरीदी गई अत्याधुनिक पैच रिपेयर मशीन का बुधवार को महापौर प्रशांत सिंघल एवं नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा द्वारा संयुक्त रूप से शुभारंभ किया गया। पूजा-अर्चना के उपरांत गूलर रोड स्थित फायर ब्रिगेड कार्यालय के निकट इस मशीन को विधिवत चलाकर अभियान की शुरुआत की गई। महापौर प्रशांत सिंघल ने कहा कि शहर की सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाना नगर निगम की प्राथमिकता है। इस मशीन के आने से अब पार्षद वार्ड श्तर पर रोस्टर बनाकर योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया जाएगा। महापौर ने अधिशासी अभियंता बिजेंद्र पाल को निर्देशित किया कि सभी 90 वार्डों में अक्टूबर माह के अंत तक अभियान चलाकर सड़कों को पूरी तरह गड्ढा मुक्त किया जाए। उन्होंने कहा कि शहर की जनता को जल्द ही गड्ढा मुक्त सड़कों का लाभ मिलेगा और आमजन को आवागमन में सुविधा होगी।

डीएम की अध्यक्षता में उद्योग एवं व्यापार बन्धु की बैठक संपन्न

✷ **एनसीआर टुडे. अलीगढ़** ✷। जिलाधिकारी संजीव रंजन की अध्यक्षता में कलैक्ट्रेट सभागार में बुधवार को जिला उद्योग एवं व्यापार बन्धु की बैठक आयोजित की गई। बैठक में उद्यमियों एवं व्यापारियों की विभिन्न समस्याओं एवं सुझावों पर विस्तार से चर्चा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। डीएम ने कहा कि अधिकारी उद्यमियों एवं व्यापारियों की शिकायतों के निश्तारण के प्रति संवेदनशील रहते हुए समयबद्धता से कार्य करना सुनिश्चित करें। बैठक में तालानगरी औद्योगिक क्षेत्र में 132 केवीए विद्युत उपकेंद्र की स्थापना के संबंध में उद्यमी लल्लू सिंह ने अवगत कराया कि ग्राम किढ़ारा में चिन्हित भूमि के संबंध में कृषकों से वार्ता हो गई है वह वाद वापिस लेने को तैयार हैं। इस पर डीएम ने यूपीसीडा को शीघ्र उपकेंद्र की स्थापना के लिए ले-आउट नियोजन की कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें। अप्रेंटिशशिप अधिनियम के तहत विगत माह 71 एवं इस माह 58 प्रशिक्षुओं को नियोजित कराया गया है। जिलाधिकारी ने प्रधानाचार्य आईटीआई को उद्यमियों से संपर्क कर प्रत्येक माह अधिकाधिक प्रशिक्षुओं को नियोजित कराने एवं उद्यमियों को इकाई की आवश्यकतानुसार शिशिक्षुओं को योजित करने के निर्देश दिए।

ढाई साल में सरकार ने 26,830.71 करोड़ रुपये का लिया लोन?

हिमाचल का कर्ज 98 हजार करोड़ के पार

शिमला, एजेंसी।
हिमाचल प्रदेश पर लगातार बढ़ता कर्ज एक गंभीर चिंता का विषय बनता जा रहा है। विधानसभा में मंगलवार को पूछे गए एक सवाल के लिखित जवाब में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खु ने प्रदेश की वित्तीय स्थिति की जानकारी दी। भाजपा विधायकों डॉक्टर जनक राज (भरमौर) और लोकेन्द्र कुमार (आनी) द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने साफ किया कि हिमाचल प्रदेश पर 31 जुलाई 2025 तक कुल 98,182 करोड़ रुपये का कर्ज है।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यह भी कहा कि मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए आने वाले महीनों में यह आंकड़ा एक लाख करोड़ रुपये को पार कर जाएगा। उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 में कर्ज के मूलधन की अदायगी के लिए 4243.57 करोड़ रुपये और ब्याज चुकाने के लिए 6738.85 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह प्रावधान कर्ज के पुनर्भुगतान कार्यक्रम के आधार पर अनुमानित है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यह भी माना कि हिमाचल प्रदेश के अपने संसाधन सीमित हैं। खर्चों के लिए प्रदेश सरकार को केंद्र सरकार पर काफी हद तक निर्भर रहना पड़ता है। 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू होने के बाद प्रदेश की केंद्र पर निर्भरता और भी ज्यादा बढ़ गई है। जीएसटी के कारण राज्य सरकार की ओर से वसूले जाने वाले कई कर समाप्त हो गए और इन्हें केंद्र में समाहित कर दिया गया। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आगे कहा कि इससे हिमाचल को बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ है। इसकी भरपाई केंद्र सरकार ने शुरुआती 5 वर्षों तक की लेकिन 1 जुलाई 2022 के बाद यह राशि मिलनी बंद हो गई। यही कारण है कि हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर दबाव और बढ़ गया है। 15वें वित्त आयोग ने हिमाचल को राजस्व घाटा अनुदान (रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट) की सिफारिश की थी। सीएम ने बताया कि वित्त आयोग के पहले वर्ष 2020-21 में हिमाचल को इसके तहत 11,431 करोड़ रुपये मिले थे। लेकिन आने वाले वर्षों में यह राशि लगातार कम होती चली गई और अंतिम वर्ष 2025-26 के लिए यह घटकर मात्र 3,257 करोड़ रुपये रह गई। जीएसटी से हुए घाटे और राजस्व घाटा अनुदान में कमी ने मिलकर राज्य को और कर्ज पर निर्भर कर दिया। मुख्यमंत्री सुक्खू ने बताया कि बीते ढाई वर्षों में प्रदेश सरकार ने विभिन्न वित्तीय संस्थाओं से कुल 26,830.71 करोड़ रुपये का कर्ज लिया है। इसमें से अकेले 20,350 करोड़ रुपये खुले बाजार से उठाए गए हैं। वहीं इस दौरान सरकार ने 8,253.94 करोड़ रुपये का कर्ज वापस भी किया है। इस प्रकार शुद्ध तौर पर प्रदेश पर 18,576.77 करोड़ रुपये का नया कर्ज चढ़ा है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने यह भी बताया कि उपरोक्त कर्ज के अतिरिक्त राज्य सरकार पर लोक लेखा के अंतर्गत सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) और अन्य मदों से भी शुद्ध कर्ज बनता है। 1 अप्रैल 2023 से 30 जून 2025 तक इस मद के अंतर्गत 2,941.89 करोड़ रुपये का कर्ज लिया गया है।

भाजपा लगातार बोल रही हमले: बता दें कि विपक्षी दल भाजपा पहले ही सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार पर लगातार कर्ज लेने और वित्तीय प्रबंधन में कमी के आरोप लगाती रही है। अब विधानसभा में पेश हुए इस आधिकारिक आंकड़े से यह साफ हो गया है कि आने वाले महीनों में हिमाचल पर कर्ज का बोझ एक लाख करोड़ रुपये के पार चला जाएगा।

आरएसएस जितना विरोध किसी संगठन ने नहीं झेला, फिर भी अपना समझकर हमने सहा: मोहन भागवत

नई दिल्ली, एजेंसी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने 100 साल पूरे होने के मौके पर देश भर में आयोजन करने वाला है। इसकी शुरुआत मंगलवार 26 अगस्त को दिल्ली से हुई है। यह इस कड़ी में पहला आयोजन है, जिसके तहत समाज के अलग-अलग वर्गों के लोगों और विदेशी प्रतिनिधियों से संघ प्रमुख मोहन भागवत संवाद करने वाला है। इसके पहले दिन मोहन भागवत ने आरएसएस के बारे में विस्तार से जानकारी दी और इसकी शुरुआत से लेकर अब तक की यात्रा के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि कुछ दशक पहले तक आरएसएस के प्रबल विरोध भी आज हमारे साथ हैं और यहां बैठे भी हैं। उन्होंने कहा कि किसी स्वयंसेवी संगठन का इतने लंबे समय तक विरोध नहीं हुआ। फिर भी हमने समाज के काम के लिए खुद को समर्पित रखा है। उन्होंने कहा कि खुद को बचाने के लिए जितना लड़ना होता था, हम लड़ते थे। लेकिन कहा जाता था कि अपना ही समाज है। एक बार ऋस्स के द्वितीय सरसंघचालक गुरुजी का जिक्र करते हुए कहा कि एक बार उनके आवास पर हमला हुआ तो कई स्वयंसेवक बचाने गए। वे प्रतिक्रिया भी करना चाहते थे, लेकिन उन लोगों को गुरुजी ने लौटा दिया। कहा कि जब इसी समाज ने सराहा तो यदि इसी समाज से कुछ और मिलता है तो वह भी स्वीकार है। मोहन भागवत ने कहा कि संघ के स्वयंसेवकों ने यही बात मन में रखी कि सभी अपने हैं। हिंदू के नाते संघ चलता है, लेकिन हिंदू का अपनापन सबके लिए है। वसुधैव कुटुम्बकम हमारा मंत्र है।

फाजिलपुरिया के दुश्मनों संग गुरुग्राम में पुलिस की भीषण मुठभेड़

गुरुग्राम, एजेंसी।
गुरुग्राम-पटौदी रोड पर गांव वजीरपुर के समीप गुरुग्राम पुलिस और बदमाशों के मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में चार आरोपियों को गोली लगी हैं। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने कुल पांच बदमाशो को दबोचा। मुठभेड़ में 18 राउंड फायर हुए हैं।

यह मुठभेड़ मंगलवार रात को सवा 12 बजे हुई। अपराध शाखा, मानेसर और सेक्टर-43 के अलावा एसटीएफ टीम की तरफ से संयुक्त रूप से कार्रवाई की गई। पुलिस को जानकारी मिली थी कि रोहित शौकिन हत्याकांड में वांछित आरोपी और सिंगर राहुल फाजिलपुर पर गोली चलाने वाले आरोपी गांव वजीरपुर के समीप से निकलेंगे। नाकाबंदी के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर गोली चला दी। इसके बाद मुठभेड़ में पांच आरोपियों में से चार आरोपियों को गोली लगी है। चारों आरोपियों को सेक्टर-10 के अस्पताल में दाखिल करवाया है। आरोपी गौतम को गोली नहीं लगी है। इसे गिरफ्तार कर लिया है। थाना सेक्टर-10ए में मामला दर्ज हुआ है। पुलिस के मुताबिक गैंगस्टर सुनील सराधानिया और दीपक नांदल के यह गुर्गे किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में निकले थे। इस मुठभेड़ में दो पुलिस कर्मी बाल-बाल बच गए। इन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट डाली हुई थी। जिन शूटरों को गोली लगी है, उनकी पहचान झज्जर निवासी विनोद पहलवान, सोनीपत निवासी पदम उर्फ राजा, शुभम उर्फ काला, आशीष उर्फ आशू के रूप में हुई है।

बच्चों के आपसी झगड़े में झटका देना बाल उत्पीड़न नहीं; सुप्रीम कोर्ट ने बताया- बाल दुर्व्यवहार में क्या-क्या जरूरी?

नईदिल्ली, एजेंसी।
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि बच्चे अगर आपस में झगड़ते हैं और उस दौरान एक-दूसरे पर हमला करते हैं या एक -दूसरे से मारपीट करते हैं और उसे देखकर अगर कोई वयस्क बच्चों को झटका देता है तो ऐसे मामूली या आकस्मिक कृत्य बाल उत्पीड़न नहीं हैं और न ही ऐसे मामलों में बाल दुर्व्यवहार का अपराध लगाया जा सकता है। जस्टिस संजय करोल और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि बाल दुर्व्यवहार की परिभाषा में नुकसान पहुँचाने, क्रूरता करने, शोषण या दुर्व्यवहार का स्पष्ट इरादा झलकना चाहिए और इसमें जानबूझकर क्रूरता या दुर्व्यवहार भी शामिल होना चाहिए।

संतोष सहदेव खजनेकर बनाम गोवा राज्य के एक मामले की सुनवाई करते हुए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि बिना किसी इरादे के गंभीर दंडात्मक परिणाम लागू करने से कानून का दायरा अनुचित रूप से बढ़ जाएगा।

बाल दुर्व्यवहार में क्या-क्या जरूरी? बार एंड बेंच की एक रिपोर्ट के मुताबिक, पीठ ने अपने फैसले में लिखा, बाल दुर्व्यवहार का अपराध अनिवार्य रूप से किसी बच्चे को नुकसान पहुँचाने, क्रूरता करने, शोषण करने या दुर्व्यवहार करने के इरादे से जुड़ा होता है, जो बच्चों के झगड़े के दौरान किसी आकस्मिक या क्षणिक कृत्य से कहीं अधिक है। जानबूझकर या लगातार दुर्व्यवहार के किसी भी सबूत के बिना, स्कूल बैग से एक साधारण हमला, बाल दुर्व्यवहार के आवश्यक तत्वों को पूरा नहीं करता है। दुर्व्यवहार के स्पष्ट इरादे या आचरण के अभाव में ऐसे गंभीर अपराध के दंडात्मक परिणामों का आह्वान करना, प्रावधान का अनुचित विस्तार होगा।

12 साल पुराने मामले में टिप्पणी-टॉप कोर्ट ने 12 साल पुराने एक मामले की सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की। पीठ फरवरी 2013 के उस मामले की सुनवाई कर रही थी, जब गोवा के तिविम स्थित एक स्कूल परिसर में बच्चों के बीच हाथापाई हुई थी। अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया था कि अभियुक्त/अपीलकर्ता ने अपने ही बेटे के स्कूल बैग से एक बच्चे को मारा, जिससे उसे मामूली चोटें आईं। निचली अदालत ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 323 (स्वेच्छा से चोट पहुँचाना), 352 (आपराधिक बल का प्रयोग) और 504 (शांति भंग करने के लिए उकसाना) के साथ-साथ गोवा बाल अधिनियम की धारा 8(2) के तहत भी दोषी ठहराया, जो बाल शोषण को अपराध मानता है। इस अधिनियम के तहत उसे एक वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई, साथ ही अन्य अपराधों के लिए छोटी-छोटी सजाएँ भी सुनाई गईं।

हाई कोर्ट ने कम कर दी थी सजा-अपील पर, बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2022 में सजा कम कर दी, यह मानते हुए कि इस कृत्य के लिए कड़ी सजा की जरूरत नहीं है। हालाँकि, उसने सभी प्रावधानों के तहत दोषसिद्धि को बरकरार रखा। इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि बिना किसी नुकसान के इरादे से स्कूल बैग से एक बार बच्चे पर वार करना अधिनियम के तहत बाल शोषण नहीं माना जाना चाहिए। अपीलकर्ता ने अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के तहत भी लाभ की मांग की।

साइकिल से विधानसभा पहुंचे सीएम नायब सैनी, मंत्री और विधायक भी थे साथ

चंडीगढ़, एजेंसी।
हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है। सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई। विधायक हॉस्टल से मुख्यमंत्री नायब सैनी, मंत्रियों और विधायकों के साथ साइकिल पर सवार होकर विधानसभा पहुंचे। स्पीकर हरविंद्र कल्याण की अपील पर नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए सभी विधायकों से साइकिल से आने का अनुरोध किया गया था। साइकिल यात्रा पर हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने कहा कि आज हरियाणा के विधायक एमएलए हॉस्टल से साइकिल चलाकर विधानसभा पहुंचे हैं। जब युवा नशे से दूर रहेंगे, तो निश्चित रूप से वे और उनका परिवार आगे बढ़ेगा। जब समाज

में ऐसा माहौल बनेगा कि हर कोई अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होगा और नशे से दूर रहेगा, तो यह राष्ट्र निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। सरकार इस मुद्दे पर गंभीरता से काम कर रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, मंत्रियों और विधायकों के साथ साइकिल चलाकर विधानसभा भवन पहुंचे। नशे के खिलाफ युवाओं को जागरूक करने के लिए स्पीकर हरविंद्र कल्याण ने सभी सदस्यों से साइकिल चलाकर आने की अपील की थी। नशा मुक्ति अभियान के तहत हरियाणा सरकार की साइक्लोथॉन यात्रा भी जारी है। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले बीजेपी विधायक दल की बैठक विधानसभा सचिवालय में हुई, जिसमें विपक्ष के सवालों का जवाब देने की रणनीति तैयार की गई। आज सदन में कांग्रेस के स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा होगी। भिवानी की शिक्षिका मनीषा की मौत और प्रदेश में कानून-व्यवस्था को लेकर कांग्रेस ने इस प्रस्ताव पर चर्चा की मांग की थी। इससे पहले 22 अगस्त को इस मुद्दे पर कांग्रेस ने भारी हंगामा किया था, जिसके कारण सदन की कार्यवाही 6 बार स्थगित करनी पड़ी थी।

मराठा आरक्षण कार्यकर्ता बगैर इजाजत प्रदर्शन नहीं कर सकते

हाईकोर्ट ने दिया मनोज जरांगे को झटका

मुंबई , एजेंसी।
बंबई उच्च न्यायालय ने गणेश उत्सव के दौरान मुंबई में कानून-व्यवस्था की स्थिति का हवाला देते हुए मंगलवार को कहा कि मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे प्राधिकारियों की पूर्व अनुमति के बिना विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते। अदालत ने साथ ही कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर अनिश्चितकाल तक कब्जा नहीं किया जा सकता।

मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे एवं न्यायमूर्ति संदीप मार्ने की पीठ ने कहा कि लोकतंत्र और असहमति साथ-साथ चलते हैं लेकिन प्रदर्शन केवल निर्धारित स्थानों पर ही होने चाहिए। पीठ ने कहा कि सरकार इस बारे में निर्णय ले सकती है कि प्रतिवादी (जरांगे) को शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के लिए नवी मुंबई के खारघर में कोई वैकल्पिक स्थान दिया जाए या नहीं, ताकि मुंबई में जनजीवन बाधित न हो। जरांगे ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) समूह के तहत मराठा समुदाय को 10 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए महाराष्ट्र सरकार को मंगलवार तक का समय देते हुए कहा था कि ऐसा नहीं होने पर वह मराठा समर्थकों के साथ मुंबई कूच करेंगे और 29 अगस्त को अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठेंगे। अदालत ने कहा कि सार्वजनिक समारोहों और आंदोलन के लिए नए नियमों के तहत अनुमति लेने के बाद शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया जा सकता है। पीठ ने कहा कि प्रतिवादी (जरांगे और उनके सहयोगी) संबंधित प्राधिकारियों से इसकी अनुमति प्राप्त करने के लिए आवेदन दायर करने के वास्ते स्वतंत्र हैं और इसके बाद सरकार कानून के प्रावधानों के अनुसार इस पर निर्णय ले सकती है। पीठ ने कहा, सरकार प्रतिवादी को शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने के लिए नवी मुंबई के खारघर में किसी वैकल्पिक स्थान की पेशकश भी कर सकती है ताकि मुंबई शहर में जीवन की गति बाधित न हो। उसने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर अनिश्चित काल तक कब्जा नहीं किया जा सकता। अदालत ने कहा कि बुधवार से शुरू हो रहे गणेश चतुर्थी उत्सव के दौरान पुलिस शहर की कानून-व्यवस्था की स्थिति को संभालने में व्यस्त रहेगी। आंदोलन को चुनौती देने वाली एमी फाउंडेशन की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान ये निर्देश दिए। महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ ने अदालत से कहा कि राज्य सरकार शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन करने के नागरिकों के अधिकार को चुनौती नहीं देती लेकिन इसका इस्तेमाल इस तरह से नहीं होना चाहिए जिससे शहर ठप हो जाए। उन्होंने कहा कि गणेश चतुर्थी उत्सव के दौरान पुलिस बल पर कानून-व्यवस्था बनाए रखने का अत्यधिक बोझ होता है।

इंडिया गठबंधन की एकता पर सवाल: ब्रजेश पाठक बोले- 11 सीटों पर अलग-अलग क्यों लड़ेगी सपा-कांग्रेस?

लखनऊ, एजेंसी।
उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने इंडिया गठबंधन की एकता पर सवाल उठाया। बृजेश पाठक ने कहा कि एमएलसी की 11 सीटों पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का अलग-अलग चुनाव लड़ना ही इंडिया गठबंधन की असलियत को उजागर करता है। उन्होंने कहा कि यह गठबंधन केवल अवसरवाद और सत्ता की लालसा पर आधारित है, इसमें न कोई वैचारिक प्रतिबद्धता है और न ही जनता के लिए कोई गंभीर सोच। ब्रजेश पाठक ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी सीपी राधाकृष्णन

प्रचंड मतों से विजयी होंगे। उन्होंने कहा कि जनता का विश्वास भाजपा और एनडीए के साथ है और यही भारतीय लोकतंत्र की सच्ची ताकत है। दरअसल प्रदेश में एमएलसी की 11 सीटों पर 2026 में होने वाले स्नातक और शिक्षक क्षेत्र के चुनाव की तैयारियां चल रही है। इनमें 5 स्नातक और 6 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल 7 दिसंबर 2026 को समाप्त हो जाएगा।

ब्रजेश पाठक ने कहा कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का बयान अंतर्विरोधों से भरा हुआ है। उन्हें कांग्रेस के काले इतिहास का अध्ययन करना चाहिए। यही कांग्रेस है जिसने देश पर आपातकाल थोपकर पूरे भारत को कैदखाने में बदल दिया था। यही नहीं, कांग्रेस ने अलग-अलग समय पर जनता द्वारा चुनी गई 90 राज्य सरकारों को बर्खास्त कर लोकतंत्र का गला घोंटने का काम किया। उन्होंने कहा कि यह भारतीय लोकतंत्र का सबसे काला अध्याय है, जिसे देश कभी भूल नहीं सकता।

ब्रजेश पाठक ने कहा कि समाजवादी पार्टी को आत्मावलोकन की आवश्यकता है। प्रदेश की सत्ता में जब-जब सपा रही, गुंडे और माफिया सत्ता के आशीर्वाद से पनपे। उन्होंने कहा कि उस दौर में पूरा प्रदेश कहता था, देख सपाई, बिटिया घबराई। यही नहीं, सपा के लोग नारा देते थे, समाजवाद का नारा है, खाली प्लॉट हमारा है। विधानसभा सत्र के दौरान दर्जनों गाड़ियों में असलहा भरकर माफिया सदन में पहुंचते थे। उस दौर में उत्तर प्रदेश को अपराधियों का चारागाह बना दिया गया था। ब्रजेश पाठक ने कहा कि समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन के लोग केवल कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं। कांग्रेस और सपा दोनों दल जनता को छलने का काम कर रहे हैं। एक ओर वे गठबंधन की बातें करते हैं और दूसरी ओर एमएलसी की 11 सीटों पर अलग-अलग मैदान में उतरते हैं। इससे साफ हो जाता है कि इंडी गठबंधन केवल दिखावा है। यह गठबंधन जनता को भ्रमित करने का एक और प्रयास है, जिसका पर्दाफाश हो चुका है।

ब्रजेश पाठक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सुचिता और पारदर्शिता की राजनीति का उदाहरण बनी है।

पूर्व राज्य सभा सांसद ने वित्त राज्य मंत्री से मुलाकात की

✷ एनसीआर टुडे. गाजियाबाद ✷। पूर्व राज्य सभा सांसद डॉ. अनिल अग्रवाल ने वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी से दिल्ली में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने जीएसटी के विषय को लेकर मंत्री से विशेष रूप से बात की। उन्होंने जीएसटी की दरों को लेकर साथ ही व्यापारियों के हित में नियम सुगम करने को लेकर सुझाव भी रखे। इस मौके पर मीडिया सलाहकार व खाद्य निगम सदस्य राहुल गोयल मौजूद रहे।

केशव चौधरी गाजियाबाद के एडिशनल सीपी बने

✷ एनसीआर टुडे. गाजियाबाद ✷। 2009 बैच के आईपीएस अधिकारी केशव कुमार चौधरी को गाजियाबाद कमिश्नरेट का एडिशनल सीपी बनाया गया है। शासन ने बुधवार को चार आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए। तबादला सूची के मुताबिक झांसी रेंज के डीआईजी रहे केशव कुमार चौधरी को गाजियाबाद कमिश्नरेट का नया एडिशनल सीपी बनाकर भेजा गया है। जबकि गाजियाबाद की एडिशनल सीपी 2010 बैच की आईपीएस अधिकारी कल्पना सक्सेना को पीएसी मेरठ सेक्टर का डीआईजी बनाया गया है। मूलरूप से दरभंगा बिहार के रहने वाले केशव कुमार चौधरी कई जिलों में कप्तान रह चुके हैं और उनकी गिनती मेहनती व ईमानदार अधिकारियों में की जाती है। उनकी गाजियाबाद में तैनाती होने के बाद कार्यक्षेत्र को लेकर पुलिस विभाग में चर्चाओं का बाजार गर्म है।

स्योहारा क्षेत्र में 7 दिन बाद लापता युवक का शव जंगल से बरामद

✷ एनसीआर टुडे. स्योहारा ✷। क्षेत्र के हसनपुर पालकी के जंगल में सोनप्रकाश उर्फ सोनू पुत्र सोननाथ सिंह उम्र 33 वर्ष का शव मिला। सद्दीखेड़ा के गांव में रहने वाले एक युवक का शव बुधवार दोपहर 3 बजे जंगल से बरामद हुआ। जानकारी के अनुसार युवक पिछले सात दिनों से लापता था, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट परिजनों ने थाने में दर्ज कराई थी। बुधवार को ग्रामीणों ने जंगल चारा लेने गए तो दुर्गंध आने पर पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच की तो युवक का शव पेड़ से लटका मिला। शव की शिनाख्त सोनप्रकाश उर्फ सोनू 33 वर्ष ग्राम सद्दीखेड़ा निवासी युवक के रूप में हुई। मृतक युवक और पत्नी में कुछ समय से चल रहा था घरेलू विवाद। 19 अगस्त को थाने में गुमशुदगी कराई गई थी दर्ज।

बिजली का करंट लगने से युवक की दर्दनाक मौत, परिवार में मचा कोह राम

✷ एनसीआर टुडे. नहटौर ✷। बीती रात ग्राम रखड़ायो में 11वीं के छात्र की बिजली के करंट लगने से मौत हो गई। जिससे परिजनों व गांव में शोक की लहर दौड़ गई और परिवार वालों में मातम छा गया। प्राप्त समाचार के अनुसार थाना क्षेत्र के ग्राम रखड़ायो निवासी हेमराज गरीबी के चलते अपना जीवन मेट्रो रिक्शा चला कर अपने परिवार का पालन पोषण करता है। रोजाना की भांति उसने अपनी रिक्शा को चार्जिंग पर लगा रखा था। देर रात उसका पुत्र आशीष कुमार उम्र 18 वर्ष शौच के लिए उठा तो उसका हाथ रिक्शा पर रखा गया। जिसमें बिजली का तार टच होने से करंट आ रहा था। जिस कारण आशीष कुमार बिजली के करंट की चपेट में आ गया। परिवार के लोग ने बिजली बंद की तब तक वह अचेत हो गया था। परिजनों ने उपचार के लिए उसे सीएचसी में भर्ती कराया। जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आशीष कुमार कक्षा एसएनएसएम इंटर कॉलेज में कक्षा 11 में पढ़ता था।

मेधावी छात्रों को किया सम्मानित

✷ एनसीआर टुडे. नहटौर ✷। एसएनएसएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मेधावी छात्रों का सम्मान समारोह का कार्यक्रम आयोजित हुआ। जिसमें अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान रायपुर एमबीबीएस में चयनित होने पर विद्यालय ने छात्र अमन सहरान एवं बीएएमएस में चयनित छात्रा कृति दुबे को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। सम्मान समारोह कार्यक्रम का शुभारम्भ स्कूल संस्थापक राजबहादुर सिंह ने मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलित करके पुष्प अर्पित कर किया। प्रबंधक ई. धनेश सिंह ने विद्यालय के इतिहास के बारे में विस्तार से प्रकाश डालते हुए छात्र-छात्राओं को अपने सर्वांगीण विकास के लिए चयनित छात्र-छात्राओं से सीख लेकर अपने भविष्य को उज्वल बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। प्रधानाचार्य डॉ दिनेश कुमार के संचालन में आयोजित कार्यक्रम में राकेश कुमार, कोरेंद्र कुमार, संजीव कुमार सैनी राहुल कुमार, शिवम कुमार, हितेश कुमार, अनुज कुमार, नाजिया, अनु, वंशिका आदि उपस्थित रहे।

मैरिस रोड पर अतिक्रमण अभियान

✷ एनसीआर टुडे. अलीगढ़ ✷। बीते कई दिनों से नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा के समक्ष मैरिस रोड चाइनीज फ़ास्ट फ़ूड पर अवैध खड़े होने वाले स्ट्रीट वेंडर्स के कारण शाम के समय जाम की स्थिति उत्पन्न हो रही थी। इससे पहले कई बार नगर निगम ने इन अवैध वेंडर्स को अतिक्रमण स्वयं हटाने की हिदायत दी लेकिन बार-बार हिदायत के बावजूद मैरिस रोड चौराहे से सेंटर पॉइंट की ओर जाने वाले रास्ते पर जगह-जगह अवैध वेंडर्स के खड़े होने के कारण आम नागरिकों को ट्रैफिक जाम की स्थिति से जूझना पड़ रहा था। जिसको देखते हुए नगर आयुक्त ने तत्काल अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध अभियान चलाने के निर्देश दिए। बुधवार शाम सहायक नगर आयुक्त वीर सिंह के नेतृत्व में कर अधीक्षक आरके कमल नगर निगम प्रवर्तन टीम द्वारा मैरिज रोड चाइनीस फास्ट फूड रोड से अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त करने की कार्रवाई की अतिक्रमण करने वालों को नगर निगम ने चेतावनी दी की दोबारा अतिक्रमण करने पर नगर निगम द्वारा कानूनी कार्रवाई करेगा।

टीबी मरीजों को पोषण पोटली बांटी

✷ एनसीआर टुडे. गाजियाबाद ✷। रेडक्रॉस सोसाइटी और इनरव्हील क्लब ने गुरुवार को 60 टीबी मरीजों को पोषण पोटली का वितरण किया। डूंडाहेड़ा के 50 बेड अस्पताल में आयोजित कार्यक्रम में इनरव्हील क्लब की गाजियाबाद ग्रेटर, कौशांबी और गोल्फलिंक इकाइयों ने अपनी भागीदारी दी। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि एसीपी प्रिया श्रीपाल कहा कि पौष्टिक भोजन लेने से दवा का असर ज्यादा होता है।

ग्रामीण नदी किनारे अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे, आखिर क्यों ?

✷ एनसीआर टुडे. बढ़ापुर ✷

क्षेत्र के गांव में गांव के दोनों और नदी होने के कारण बरसात के दिनों में पूरे दिन बैठकर घरों में लोग नदी का बहाव कम होने का इंतजार करते हैं इसके चलते कभी-कभी अनहोनी भी हो जाती है। लोग जान जोखिम में डालकर नदियों को पार करते हैं।

बढ़ापुर क्षेत्र के उत्तर में बहने वाली पहाड़ी नदी जब अपने उफान पर होती है तब उस नदी को पार करने के लिए ग्रामीणों को काफी जोखिमों का सामना करना पड़ता है गौरतलब है कि गांव काशीवाला, बहेड़ी, धरमुवाला, चकउदयचंद, सरदारपुर व रसीदपुर अन्य तमाम गांव के लोग दोनों और नदियों से घिरे हैं बरसात के दिनों में जब बारिश पड़ती है और नदियां उफान पर होती हैं तब इन तमाम गांव के लोग कस्बे व मुख्यालय तक पहुंचाने के लिए नदियों का पानी उतरने का इंतजार करते हैं।

यहां तक की कभी-कभी गांव में बीमारों की नदी में पानी होने की वजह से मौत भी हो जाती है। ताजा मामला अभी लगभग 20 दिन पूर्व एक बीमार की अचानक गांव में तबीयत खराब हुई व बीमार को कस्बे तक ले जाने के लिए कई घंटे पानी कम होने का इंतजार करना पड़ा जिससे बीमार की नदी के किनारे ही मौत हो गई।

आधा दर्जन गांवों के लोग नदी पार करने के लिए बरसात के दिनों में कस्बे में मुख्यालय तक पहुंचाने के लिए पूरा दिन पानी उतरने का इंतजार करते हैं जिससे तमाम दुर्घटनाएं गांव में ही हो जाती हैं बीमारों को गांव में ही रहना पड़ता है। बैल बुग्गियों ट्रैक्टर ट्रालियों पर लाद कर लोग अपनी बाइकों को जान जोखिम में डालकर नदी पार कराते हैं। कभी-कभी पानी बहाव ज्यादा होने की वजह से बैल बुग्गी भी पलट जाती है। और लोगों की जान पर खतरा बनता है गांव के तैराकों के द्वारा लोगों को निकाला जाता है। ऐसी ही तमाम परेशानियों को लेकर ग्रामीण अक्सर प्रशासनिक अधिकारियों राजनेताओं से गांव की नदी पर पुल के निर्माण की मांग अक्सर करते रहें हैं।लेकिन जब ग्रामीणों को इंसाफ नहीं मिला आज तक पुल का निर्माण नहीं हुआ तमाम झूठे आश्वासनों के बाद ग्रामीणों का गुस्सा फूटा, ग्रामीणों ने नदी के किनारे अनिश्चितकालीन धरने का प्रोग्राम बना लिया 25 अगश्त को ग्रामीणों ने उप जिलाधिकारी नगीना को ज्ञापन सौंपा जिसमें उन्होंने दो दिन के बाद नदी के किनारे अनिश्चित कालीन धरने का चेतावनी दी। लेकिन प्रशासन की नींद नहीं खुली तब तमाम गांव के लोग इकट्ठा हुए और नदी के किनारे धरने पर बैठ गए ग्रामीणों ने बताया कि धरना अनिश्चितकालीन है जब तक नदी पर पुल बनने की कोई पुख्ता आश्वासन या काम नहीं लगेगा तब तक ग्रामीण धरने पर बैठे रहेंगे चाहे इसके लिए कितना भी समय लगे।

आधा दर्जन इन गांवों के मार्ग पर पुल नहीं होने के कारण गांव के तमाम विद्यार्थी बालिकाएं कस्बे तक अपने स्कूलों विद्यालयों को नहीं पहुंच पाते हैं। बीमारों को उचित उपचार नहीं मिल पाता समय पर,दो वर्ष पूर्व 15 अगश्त को नदी में जलश्तर बढ़ा हुआ था। गांव की बालिकाएं कस्बे के विद्यालय नहीं पहुंच सकी और तमाम ग्रामीण व बालिकाओं ने नदी के पानी में खड़े होकर राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। जिसकी गूंज पूरे प्रदेश में पहुंची थी उसके बाद कुछ प्रशासनिक अधिकारी पुल के निर्माण के लिए जांच करने आए लेकिन सारे वादे कागजों में धरे रह गए।

अब ग्रामीणों का कहना है बरसात के दिनों में गांव के विद्यार्थी कस्बे तक नहीं पहुंच पाते बीमार अस्पताल तक नहीं पहुंच पाते जरूरी सरकारी कार्यों से मुख्यालय एवं तहसीलों तक किसान नहीं पहुंच पाते कस्बे से घरेलू खाने के समान गांव तक नहीं पहुंच पाता ऐसे में ये ग्रामीण आखिर करें तो क्या करें। कौन इसका जिम्मेदार है ग्रामीणों का कहना है क्या हम लोगों को आजादी का लाभ नहीं मिलेगा।

बाइक की टक्कर से एक की मौत

✷ एनसीआर टुडे. गाजियाबाद ✷

लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र में दिल्ली सहारनपुर रोड पर साइकिल से घर लौट रहे व्यक्ति को अज्ञात बाइक सवार ने टक्कर मार दी। पुलिस ने परिजनों को सूचना देकर घायल को जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया।

उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। मृतक के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात बाइक सवार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। लोनी थाना क्षेत्र की इकराम नगर कॉलोनी निवासी रियाजुद्दीन के पिता रहमत अली दिल्ली गांधीनगर में नौकरी करते थे।

रियाजुद्दीन ने बताया कि पिता प्रतिदिन साइकिल से गांधीनगर आते जाते थे। 19 अगश्त शाम के समय साइकिल पर घर लौटते समय दिल्ली सहारनपुर रोड स्थित भारतीय स्टेट बैंक के सामने अज्ञात बाइक चालक ने पिता की साइकिल में टक्कर मार दी। घटना को अंजाम देने के बाद बाइक चालक मौके से फरार हो गया जबकि उनके पिता गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों ने मामले की सूचना पुलिस को दी।

मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल के परिजनों को सूचना देकर उसे जीटीबी अस्पताल में भर्ती करवाया। 25 अगश्त को अस्पताल में उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने पुलिस को शिकायत देकर आरोपी अज्ञात बाइक चालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।

सीओ अंकुर विहार ज्ञान प्रकाश राय ने बताया कि मृतक के पुत्र की शिकायत पर अज्ञात बाइक चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी।

जसपुर मार्ग पर एनएच-74 ग्राम जिकरीवाला उर्फ भवानीपुर के पास बाइक और ट्रैक्टर की जोरदार भिड़ंत

एनसीआर टुडे. अफजलगढ़। बाइक सवार और ट्रैक्टर की जोरदार भिड़ंत में दो युवक घायल हो गए। एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। ग्राम मेघपुर निवासी कफील अहमद पुत्र अली हुसैन अपने साथी नईम अहमद पुत्र अब्दुल मजीद निवासी मोहल्ला नेजोसराय के साथ बाइक से जसपुर मजदूरी करने जा रहे थे।

जैसे ही उनकी बाइक जिकरीवाला गांव के पास पहुंची, अचानक सामने आए ट्रैक्टर से टक्कर हो गई। हादसे में दोनों युवक सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों ने 108 एंबुलेंस की मदद से दोनों घायलों को अफजलगढ़ सीएचसी पहुंचाया। जहां से डॉक्टर ने कफील की हालत नाजुक होने पर हायर सेंटर रेफर कर दिया। वहीं नईम को एक निजी अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया। पुलिस का कहना है तहरीर मिलने पर मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी।

पत्नी के हत्यारे को हुआ आजीवन कारावास, छह महीने में सजा

✷ एनसीआर टुडे. अलीगढ़ ✷

थाना अतरौली क्षेत्र के रायपुर स्टेशन के पास 6 महीने पहले हुई महिला की हत्या में कोर्ट ने दोषी पति को सजा सुनाई है। शराब के नशे में पत्नी की हत्या करने वाले दोषी को कोर्ट ने आजीवन करावास की सजा दी है। दोषी ने अपनी पत्नी की निर्मम हत्या कर दी थी। घटना के दिन दोषी शराब पीकर आया था और उसकी पत्नी ने इस बात का विरोध किया था।

जिस पर दोषी आग बबूला हो गया था और उसने अपनी पत्नी के साथ मारपीट शुरू कर दी थी। उसकी पत्नी अपनी जान बचाते हुए पड़ोसी के घर में घुस गई थी। जिस पर दोषी उसे वहां से बाल पकड़कर खींच लाया था और फावड़े से काट दिया था।

डीजीसी क्राइम अमर सिंह तोमर ने बताया कि घटना 24 जनवरी 2025 की है। मृतका के पिता ने अतरौली थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। मूल रूप से बांदा निवासी राकेश ने बताया था कि उन्होंने अपनी बेटी सरवन की शादी 9 साल पहले अलीगढ़ में की थी। सरवन का विवाह बरला निवासी भोला उर्फ उमेश चंद्र के साथ हुआ था। जिसके बाद दोनों अतरौली में आकर रह रहे थे।

उन्होंने बताया कि उन्हें फोन के जरिए सूचना मिली है कि उनके दामाद ने बेटी की हत्या कर दी है। पिता की तहरीर मिलने के बाद पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी थी और हत्या के दूसरे दिन ही आरोपी गिरफ्तार हो गया था।

डीजीसी क्राइम ने बताया कि 4 जुलाई को इस मामले का चार्ज बना है। जिसके बाद कोर्ट में ट्रायल शुरू हो गया। इसमें पड़ोसियों की गवाही अहम रही। पड़ोस में रहने वाली महिलाओं ने बताया कि घटना के दिन सरबन उनके घर भागकर आ गई थी और खुद को बचाने की गुहार लगा रही थी। मृतका सरबन के साथ उसकी बेटी भी थी। तभी दोषी पति हाथ में फावड़ा लेकर वहां आया और सरबन को बाल पकड़कर खींचते हुए ले गया।

इसके बाद उनसे सरबन के गले में फावड़े से वार किया और उसकी हत्या करके फरार हो गया। मुहल्ले के लोगों ने ही पुलिस को मामले की जानकारी दी। मामले का ट्रायल जिला जज अनुपम कुमार की कोर्ट में चल रहा था।

गवाहों के बयान सुनने के बाद उन्होंने दोषी पति भोला उर्फ उमेश चंद्र को आजीवन कारावास और 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट के फैसले के बाद पुलिस ने दोषी को जेल भेज दिया है।

डाकघर में आधार कार्ड अपडेट का घोटाला

✷ एनसीआर टुडे. अलीगढ़ ✷

टप्पल डाकघर में आधार कार्ड सेवाओं को लेकर भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। डाकघर में कार्यरत कर्मचारी रोहित रावत पर आधार कार्ड बनाने और अपडेट के नाम पर अवैध वसूली का आरोप है।

शिकायतकर्ताओं के अनुसार, कर्मचारी आधार कार्ड की सेवाओं के लिए 500 से 3000 रुपए तक की रिश्वत मांग रहा है। वह लोगों को यह कहकर लौटा देता है कि साइट एक महीने से बंद है। लेकिन पैसे देने पर तुरंत काम हो जाता है।

टप्पल निवासी राजू चौधरी ने बताया कि बायोमैट्रिक अपडेट के लिए कई बार चक्कर लगाने पर भी साइट बंद होने की बात कही गई। सालपुर के दीवान ने बताया कि जन्मतिथि सुधार के लिए उनसे 3,500 रुपए मांगे गए। उन्होंने 3000 रुपए दे दिए, लेकिन अभी तक काम नहीं हुआ।

एक अन्य युवक अरुण ने भी नए आधार कार्ड के लिए 1000 रुपए की मांग का आरोप लगाया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि रोहित रावत के खिलाफ पहले भी कई शिकायतें हो चुकी हैं।

लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ितों ने टप्पल थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। ग्रामीणों की मांग है कि डाक विभाग तुरंत जांच कर

अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के तत्वावधान में विचार गोष्ठी का आयोजन

✷ एनसीआर टुडे. चांदपुर ✷

अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के तत्वावधान में चक्रवर्ती गुर्जर-प्रतिहार सम्राट राजा मिहिर भोज की 1189 वीं जयन्ती पर विचार गोष्ठी का आयोजन कर याद किया गया।

तहसील क्षेत्र के मंझौला गुर्जर चौराहा स्थित एस के एम पब्लिक इन्टर कॉलेज के सभागार में आयोजित विचार गोष्ठी को सम्बोधित करते हुए अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं प्रचार मंत्री डॉ० मनोज कटारिया ने कहा कि चक्रवर्ती गुर्जर-प्रतिहार सम्राट राजा मिहिर भोज गुर्जर-प्रतिहार वंश के सबसे शक्तिशाली सम्राटों में से एक थे।

उनका साम्राज्य उत्तर भारत के विशाल भू-भाग में फैला हुआ था और कन्नौज उनकी राजधानी थी। उस समय कन्नौज पर अधिकार करना साम्राज्य की प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता था। सम्राट मिहिर भोज ने अपने साम्राज्य को पश्चिम में गुजरात व राजस्थान से लेकर पूर्व में बंगाल तक और उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी तक फैलाकर (836-885 ई०) 49 वर्ष तक शासन किया।

डॉ० मनोज कटारिया ने कहा कि धार्मिक दृष्टि से सम्राट मिहिर भोज विष्णु के वराह अवतार के उपासक थे। उन्होंने "आदि-वराह" की उपाधि धारण की और वे वैष्णव परंपरा के समर्थक थे, परंतु उनके साम्राज्य में अन्य धर्मों एवं परंपराओं को भी स्थान प्राप्त था। उनके शासनकाल में कला, संस्कृति एवं प्रशासनिक व्यवस्था की विशेष प्रगति हुई।

चक्रवर्ती गुर्जर-प्रतिहार सम्राट राजा मिहिर भोज को एक महान शासक के रूप में स्मरण किया जाता है, जिन्होंने न केवल अपने साम्राज्य को सुदृढ़ किया, बल्कि उत्तर भारत में राजनैतिक स्थिरता और सांस्कृतिक उत्थान का मार्ग भी प्रशश्त किया।

समाज सेवी अनिल कुमार उर्फ बबलू की अध्यक्षता एवं प्रधानाचार्य शिवकुमार कटारिया के संचालन में आयोजित कार्यक्रम में डायरेक्टर बिजेन्द्र सिंह उर्फ भोलू, नवनीत कटारिया, नरेश कुमार, अनिल कुमार, परम सिंह, मेघराज सिंह, ब्रह्मदेव सिंह, सुमन देवी, सुनील कुमार आदि ने विचार व्यक्त करते हुए नमन किया।

कार्यक्रम में बड़ी तादाद में क्षेत्र के गणमान्य नागरिक, शिक्षक- शिक्षिकाएं एवं छात्र- छात्राएं उपस्थित रहे।

प्रेम विवाह करने वाली युवती को जान का खतरा

✷ एनसीआर टुडे. अलीगढ़ ✷

थाना हरदुआगंज क्षेत्र में एक विवाहिता ने अपने मायके पक्ष के लोगों से खुद को जान का खतरा बताया है। पीड़िता ने कुछ दिन पहले अपने प्रेमी के साथ प्रेम विवाह किया था और अपना धर्म परिवर्तन भी कर लिया था। इसके बाद से उसके परिवार के लोग उससे नाराज हैं।

पीड़िता का कहना है कि मायके के लोग उसे जान से मारना चाहते हैं और लगातार उस पर और उसके पति के ऊपर हमला भी कर रहे हैं। पीड़िता ने सारे मामले की शिकायत एसएसपी से मिलकर की है और न्याय की गुहार लगाई है। वहीं महिला की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच भी शुरू कर दी है।

दौलतपुरा निवासी सौबी ने 26 अगश्त को बडौला निवासी गौरव के साथ प्रेम विवाह किया था। दोनों ने घर से भागकर कोर्ट मैरिज कर ली थी। शादी होने के बाद सौबी ने सनातन धर्म अपनाते हुए अपना नाम भी बदलकर सोनिया रख लिया था।

वहीं सौबी के परिवार के लोग उसे ढूंढ रहे थे और पुलिस को शिकायत की थी। घटना के बाद से ही युवती का परिवार लगातार उससे नाराज है। अब युवती ने आरोप लगाया है कि उसके पिता और भाई, उसे और उसके पति को जान से मारना चाहते हैं। लोकल पुलिस भी उनके साथ मिली हुई है और उन्होंने घर में आकर तोड़फोड़ की।

वहीं पुलिस ने गौरव के भाई को भी हिरासत में ले लिया है। एसएसपी से न्याय की गुहार लगाने के बाद सौबी उर्फ सोनिया कोर्ट पहुंची। यहां उसके पिता और परिवार के लोग भी पहुंच गए। जिसके बाद दोनों पक्षों में जमकर कहासुनी भी हुई।

वहीं पुलिस ने बीच में पकड़कर बीच बचाव कराया और मामले की जांच शुरू कर दी। सोनिया ने बताया कि वह बालिग है और अपनी मर्जी से प्रेमी के साथ कोर्ट मैरिज की है। सीओ अतरौली राजीव द्विवेदी ने बताया कि युवती बालिग है और उसने कोर्ट मैरिज की है। उसकी शिकायत के आधार पर मामले की जांच की जा रही है और उसके बयान दर्ज किए जा रहे हैं।

उन्होंने बताया कि जांच के आधार पर जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

अज्ञात वाहन की टक्कर से किसान की मौत

एनसीआर टुडे. अलीगढ़। बुधवार सुबह करीब 11 बजे नानऊ सांकरा मार्ग स्थित गांव हैवतपुर कोटरा के पास कैंची पुलिया के समीप बाइक सवार तीन किसानों को अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दो गंभीर रूप से घायल हो गए।

जिला कासगंज थाना सोरों के गांव इस्माइलपुर निवासी गंगा प्रसाद पुत्र चेतराम, अच्छन पुत्र अल्लाहनूर और प्रवेश कुमार पुत्र रामेश्वर सिंह पास में खाद ना मिलने के कारण बाइक से जिला अलीगढ़ के कस्बा छर्रा खाद लेने जा रहे थे। तभी हैवतपुर कोटरा के पास कैंची पुलिया के समीप अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही तीनों सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को एंबुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र छर्रा भेजा, जहां चिकित्सकों ने प्रवेश कुमार को मृत घोषित कर दिया।

युवाओं को स्वरोजगार दिलाने में बाधा न बने बैंक: डीएम

✷ एनसीआर टुडे. अलीगढ़ ✷

जिलाधिकारी संजीव रंजन की अध्यक्षता में कलैक्ट्रेट सभागार में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना अंतर्गत बैंकर्स की बैठक आहूत की गई।

बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने बैंकर्स को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं के संचालन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि बैंकर्स सहयोग नहीं करते हैं तो उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

बैठक में संयुक्त आयुक्त उद्योग बीरेंद्र कुमार ने अवगत कराया कि योजना में अलीगढ़ जिले का प्रदर्शन निराशाजनक है।

विभाग द्वारा विभिन्न बैंकों को 3297 आवेदन पत्र भेजे गए थे, जिनमें से 1510 को निरश्त, 938 स्वीकृत एवं केवल 830 पर ऋण वितरण किया गया। ऑडिट में पाया गया कि 70 प्रतिशत आवेदन पत्र गलत तरीके से रिजेक्ट किए गए हैं। कई मामलों में आवेदकों को 5 लाख की जगह केवल 40-50 हजार का ऋण लेने के लिए बाध्य किया गया।

डीएम ने कहा कि सीएम युवा उद्यमी विकास योजना का उद्देश्य युवाओं को स्वरोजगार स्थापित कर आर्थिक रूप से सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना की मॉनिटरिंग मा0 मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव श्तर से की जाती है। इसलिए बैंकर्स की जिम्मेदारी है कि वे संवेदनशीलता के साथ प्रत्येक पात्र आवेदक को ऋण उपलब्ध कराएं। बैठक में जिलाधिकारी ने बैंकवार समीक्षा करते हुए प्रत्येक माह के लक्ष्य तय कर उनकी पूर्ति अनिवार्य करने के निर्देश दिए।

उन्होंने लक्ष्य पूरा न करने वाले बैंकर्स के विरुद्ध उनके सीएमडी को पत्र लिखने के साथ ही मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई करने को भी कहा। साथ ही निरश्त किए गए आवेदन पत्रों को दोबारा संबंधित बैंक में भेजने के निर्देश भी दिए गए।

बैठक के दौरान केनरा बैंक के जिला समन्वयक को लगातार बिना तैयारी बैठक में उपस्थित होने पर बाहर का राश्ता दिखाया गया।

जिलाधिकारी के सख्त रुख को देखते हुए सभी बैंकर्स ने आश्वश्त किया कि बिना उचित कारण के रिजेक्शन नहीं किया जाएगा, शाखा प्रबंधक एवं फील्ड ऑफिसर क्षेत्र में जाकर जांच करेंगे और अधिकाधिक युवाओं को ऋण स्वीकृत कराया जाएगा।

डीएम ने एसबीआई को अगश्त मासांत तक 250, सितम्बर मासांत तक 450 एवं अक्टूबर मासांत तक 650 पात्र आवेदकों को ऋण वितरित करने के निर्देश दिए।

इसी प्रकार पीएनबी को क्रमशः 250, 450 एवं 520, ग्रामीण बैंक ऑफ आर्यावर्त को 150, 300 एवं 540, केनरा बैंक को 150, 250 एवं 480, एचडीएफसी को 50, 100 एवं 180 के साथ ही अन्य बैंकर्स के लिए भी अक्टूबर माह तक के लक्ष्य निर्धारित कर ऋण वितरण की कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

सपाइयों और पुलिस में नोंकझोंक, खींचतान में इंस्पेक्टर की वर्दी फटने से बची

✷ एनसीआर टुडे. अलीगढ़ ✷

प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूलों को मर्ज करने के विरोध में समाजवादी पार्टी ने बुधवार को कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान सपाई सीएम योगी का हाथ में चूड़ी पहने हुए का पुतला जलाना चाहते थे। धरना स्थल पर ही वह सीएम का पुतला जलाने लगे।

इसके बाद वहां मौजूद पुलिस कर्मियों और सपाइयों के बीच जमकर नोंकझोंक और खींचतान हुई। सिविल लाइंस थाना प्रभारी पंकज मिश्रा के साथ पुलिस कर्मियों ने जैसे-तैसे करके सीएम का पुतला सपाइयों से छीन लिया। इस खींचतान में इंस्पेक्टर के हाथ का बैच खींच गया। स मा ज वा दी पार्टी की जि ला ध्य क्ष लक्ष्मी धनगर के साथ बड़ी संख्या में सपाई 12 बजे कलेक्ट्रेट पर इकट्ठा हुए। पहले उन्होंने सरकार पर जमकर प्रहार किए और नारेबाजी की। इसके बाद वह कलेक्ट्रेट के सामने ही टेंट लगाकर बैठ गए और धरना शुरू कर दिया।

धरना प्रदर्शन के दौरान ही उनका पुतला फूंकने का भी प्लान था। लेकिन सीएम के पुतले को लेकर पुलिस पहले से ही एलर्ट थी। जैसे ही सपाइयों ने पुतला जलाने की कोशिश की, पुलिस कर्मियों ने सड़क पर ही उन्हें दौड़ाकर पकड़ लिया और पुतले में आग नहीं लगाने दी। कलेक्ट्रेट में धरने के बाद सपाइयों ने प्रशासन के माध्यम से सरकार को ज्ञापन भेजकर स्कूलों का एकीकरण रद्द करने की मांग की है। एसीएम को ज्ञापन सौंपकर उन्होंने सरकार के सामने अपनी मांगें रखी हैं। वहीं दूसरी ओर सपाइयों का धरना भी अभी जारी है।

सपाइयों के प्रदर्शन और धरने को देखते हुए कलेक्ट्रेट पर पुलिस बल को मुश्तैद कर दिया गया है, जिससे कि किसी तरह की अप्रिय घटना न हो। अधिकारियों ने सपाइयों को आश्वसन दिया है कि उनकी मांगों को सरकार तक भेजा जाएगा। प्रदर्शन के दौरान जिलाध्यक्ष लक्ष्मीधनगर, पूर्व जिलाध्यक्ष गिरीश यादव, अज्जू इश्हाक, समेत बड़ी संख्या में पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे।

संपादकीय

'पशु प्रेमियों' के देश में वृद्ध जनों की दुर्दशा

इन दिनों भारत में सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक आवारा कुत्तों को लेकर बड़ी बहस छिड़ी हुई है। वैसे तो आवारा कुत्तों के पक्ष में और इसके ख़िलाफ़ भारतीय समाज पहले से ही विभाजित है। परन्तु इस विषय को लेकर ताज़ातरीन बहस की शुरुआत उस समय हुई जब माननीय सर्वोच्च न्यायलय ने गत 11 अगस्त को दिल्ली-एनसीआर अर्थात दिल्ली, ग़ाज़ियाबाद, नोएडा, फ़रीदाबाद, गुरुग्राम में आवारा कुत्तों की समस्या पर स्वतः संज्ञान लेते हुये दिल्ली नगर निगम व अन्य नगर निकायों को निर्देश दिया था कि वे 8 सप्ताह के भीतर सभी आवारा कुत्तों को पकड़ें और उन्हें स्थायी रूप से शेल्टर होम्स या पाउंड्स में रखें। अपने इस आदेश में सर्वोच्च न्यायलय ने कुत्तों को वापस सड़कों पर छोड़ने पर भी रोक लगाई थी। चूँकि कुत्तों के काटने की घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही थी ख़ासकर बच्चों और बुज़ुर्गों पर कुत्तों के हमलों की शिकायतें बढ़ती जा रही थीं और इस संबंध में केवल दिल्ली में ही हज़ारों मामले दर्ज हो चुके थे और रेबीज़ से होने वाली मौतों में भी वृद्धि होती जा रही थी इसी के मद्देनज़र सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्वतः संज्ञान लेते हुये यह आदेश दिए गये थे। अपने आदेश में न्यायलय ने कहा था आर्टिकल 21 के तहत जीवन का अधिकार व नागरिकों की सुरक्षा प्राथमिकता है। इसी के साथ अदालत ने यह निर्देश भी दिया था कि आवारा कुत्तों के लिये शेल्टर होम्स बनाए जाएँ व कुत्तों को पकड़ने के लिए संसाधन भी जुटाये जायें। यहाँ तक कि इस अदालती निर्देश में बाधा डालने वाले पशु प्रेमियों व ग़ैर सरकारी संगठनों को दण्डित करने का भी निर्देश दिया गया था।

परन्तु इस जनहितकारी अदालती आदेश के बाद तो देश के 'कुत्ता प्रेमियों' में कोहराम मच गया। मानव सुरक्षा को दरकिनार कर 'कुत्ता प्रेमियों' द्वारा तर्क दिया जाने लगा कि शेल्टर होम्स में कुत्ते असुरक्षित रहेंगे। क्योंकि इंफ़्रास्ट्रक्चर की कमी के चलते लाखों कुत्तों को शेल्टर में रखना अव्यावहारिक है। इससे लाखों कुत्तों को क़ैद करने और संभावित रूप से मारने का ख़तरा बढ़ेगा। इसे एनिमल बर्थ कंट्रोल (डॉग्स) रूल्स, 2023 का उल्लंघन बताया जाने लगा। पशु प्रेमियों द्वारा इस अदालती आदेश को 'बहुत कठोर' बताया जाने लगा। जगह जगह धरने प्रदर्शन शुरू हो गये। कुत्ता प्रेमी अदालती आदेश की अवहेलना करने पर आमादा दिखाई देने लगे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर 22 अगस्त 2025 को एक संशोधित आदेश जारी किया। सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने 11 अगस्त 2025 के मूल आदेश में बदलाव करते हुये नये निर्देश जारी किये।

इन संशोधित निर्देशों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया कि कुत्तों को पकड़ना जारी रखें, लेकिन उन्हें स्टरलाइज़ (नसबंदी), डीवार्म (कीड़े निकालना) तथा वैक्सीनेट (टीका लगाना) करें। ग़ैर -आक्रामक (नॉन-एग्रेसिव) और ग़ैर-संक्रमित (रेबीज मुक्त) कुत्तों को उसी इलाक़े में वापस छोड़ें। केवल रेबीज संक्रमित या आक्रामक कुत्तों को ही अलग शेल्टर में रखें। जबकि सड़कों पर खाना खिलाना प्रतिबंधित क़रार दिया गया। अदालत ने प्रत्येक वार्ड में समर्पित फ़ीडिंग स्पॉट बनाने व नोटिस बोर्ड लगाने का भी निर्देश दिया। यह भी निर्देशित किया गया कि पशु प्रेमी कुत्तों को गोद ले सकते हैं, लेकिन उन्हें सड़क पर नहीं छोड़ सकते। इन निर्देशों में बाधा डालने वाले कथित 'पशु प्रेमियों' पर व्यक्तिगत तौर पर 25, 000 तथा ग़ैर सरकारी संगठनों पर 2, 00, 000 रूपये जुर्माना लगाने का निर्देश दिया गया। जुर्माने से वसूली गई यह धनराशि शेल्टर होम बनाने में इस्तेमाल होगी। यह संशोधित आदेश पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 और एबीसी रूल्स, 2023 पर आधारित है, जो पशुओं को मारने के बजाय स्टरलाइज़ेशन और वैक्सिनेशन पर ज़ोर देता है।

परन्तु समाज के सामने सबसे बड़ी समस्या यह है कि नागरिक सुरक्षा और पशु कल्याण के मध्य संतुलन कैसे बिठाया जाये। पशु प्रेमी होने में कोई बुराई नहीं। परन्तु क्या पशु प्रेम विशेषकर 'कुत्ता प्रेम' को मानव प्रेम पर तरजीह दी जा सकती है? देश में रोज़ाना कुत्ते के काटने से सैकड़ों लोग बुरी तरह घायल होते हैं। अनेक की मौत हो जाती है। इनहीं कुत्तों की वजह से अनेक दुर्घटनायें होती हैं। स्कूल जाते बच्चों पर व असहाय बुज़ुर्गों पर आवारा कुत्ते घातक हमले कर देते हैं। उस समय इन कुत्तों से प्यार करने वाला कोई भी पशु प्रेमी सामने नहीं आता। उल्टे कई बार तो पीड़ति राहगीरों पर ही यह दोष मढ़ दिया जाता है कि वह उधर से गुज़रा ही क्यों? या फिर पहले उसने कुत्ते को छेड़ा होगा आदि आदि। हद तो यह है कि कई बार यही कुत्ते अपने 'कुत्ता प्रेमी ' को ही काट लेते हैं।

निश्चित रूप से कुत्तों को दोष इसलिए नहीं दिया जा सकता कि उनकी प्रवृति ही हिंसक है। इसलिये कुत्तों के काटने भोंकने या उनके पीछे दौड़ने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। हालांकि कुत्तों की वफ़ादारी से भी इंकार नहीं किया जा सकता। कुत्तों को तो मनुष्य से भी अधिक वफ़ादार माना जाता है। परन्तु उनकी हिंसक प्रवृत्ति को नकारना और कुत्ता प्रेम की शर्त पर मानव सुरक्षा से समझौता करना भी तर्कसंगत नहीं।

इसी संदर्भ में एक बात और भी ध्यान देने योग्य है कि जिस तरह सर्वोच्च न्यायलय के गत 11 अगस्त के आदेश के बाद देश के कुत्ता प्रेमी सड़कों पर उतर आये और अपने पशु प्रेमी होने का प्रदर्शन करने लगे यहाँ तक कि कई कुत्ता प्रेमी तो अदालती आदेश को लेकर रोते पीटते भी दिखाई दिये वास्तव में यदि इसी स्तर पर समग्र भारतीय समाज में मानव प्रेम की भावना होती तो शायद आज देश में कहीं भी वृद्धाश्रम की ज़रुरत न होती।

वृंदावन में लाखों विधवाएं अपने भाग्य पर आंसू न बहा रही होतीं। अयोध्या, मथुरा व काशी जैसे अनेक धर्म स्थान बुज़ुर्ग व असहाय भिखारियों से भरे न होते। देश के स्टेशन व फ़ुट पाथ पर बड़ी संख्या में निराश्रित लोग नज़र न आते। यानी 'पशु प्रेमियों' के इस देश में कम से कम वृद्ध जनों की ऐसी दुर्दशा देखने को तो न मिलती?

आर्थिक ब्रह्मास्त्र है स्वदेशी

डा. वरिंदर भाटिया

देश में अमरीका के हठी रुख के कारण केंद्र द्वारा स्वदेशी अपनाने का आह्वान किया गया है। यह आह्वान एक महत्वपूर्ण उद्घोष है, ताकि अमरीका की कुत्सित आर्थिक नीतियों को गांधीगिरी से माकूल जवाब दिया जा सके। स्वदेशी का अर्थ है 'अपने देश में निर्मित वस्तुओं का उपयोग करना और विदेशी वस्तुओं के उपयोग से बचना।'

इसका उद्देश्य ग्राम या देश के अधिकतम लोगों द्वारा बनाई गई वस्तुओं को खरीदना और इस्तेमाल करना होता है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो और विदेशी वस्तुओं पर निर्भरता कम हो। साधारण शब्दों में, स्वदेशी का अर्थ है अपने देश की चीजों का समर्थन करना और विदेशी चीजों से बचना।

इस विचार को मुख्यतः स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीयों में बढ़ावा दिया गया था ताकि विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार से देश की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके। वर्ष 1905 के बंग-भंग विरोधी जनजागरण से स्वदेशी आंदोलन को बहुत बल मिला।

यह 1911 तक चला और गांधी जी के भारत में पदार्पण के पूर्व सभी सफल आंदोलनों में से एक था। अरविंदो घोष, रवींद्रनाथ ठाकुर, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय स्वदेशी आंदोलन के मुख्य उद्घोषक थे। आगे चलकर यही स्वदेशी आंदोलन महात्मा गांधी के स्वतंत्रता आंदोलन का भी केन्द्र-बिन्दु बन गया। राष्ट्रपिता ने इसे 'स्वराज की आत्मा' कहा था। 'स्वदेशी' का विचार कांग्रेस के जन्म से पहले ही दे दिया गया था। जब 1905 ईस्वी में बंग-भंग हुआ, तब स्वदेशी का नारा जोरों से अपनाया गया। उसी वर्ष कांग्रेस ने भी इसके पक्ष में मत प्रकट किया। देशी पूंजीपति उस समय मिलें खोल रहे थे, इसलिए स्वदेशी आंदोलन उनके लिए बड़ा ही लाभदायक सिद्ध हुआ। भारत में स्वदेशी का पहले-पहल नारा बंकिमचन्द्र चट्टोपाध्याय ने 1872 ईस्वी में ही विज्ञानसभा का प्रस्ताव रखते हुए दिया था। उन्होंने कहा था, 'जो विज्ञान स्वदेशी होने पर हमारा दास होता, वह विदेशी होने के कारण हमारा प्रभु बन बैठा है, हम लोग दिन-ब-दिन साधनहीन होते जा रहे हैं।'

अगस्त 1905 में कलकत्ता के टाउनहॉल में एक विशाल बैठक आयोजित की गई जिसमें स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई। मैनचेस्टर में निर्मित कपड़ों तथा लिवरपूल के नमक जैसे सामानों के बहिष्कार का संदेश प्रचारित किया गया।

इसी कड़ी में बंगाल के लोगों ने वंदे मातरम् गीत गाकर व्यापक विरोध प्रदर्शित किया। और रवीन्द्रनाथ टैगोर द्वारा 'आमार शोनार बांग्ला' की रचना की गई। हालांकि यह आंदोलन मुख्य रूप से बंगाल तक ही सीमित था, लेकिन भारत के कुछ अलग-अलग हिस्सों में भी इसका प्रसार देखा गया जैसे बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में पूना और बॉम्बे में, लाला लाजपत राय और अजीत सिंह के नेतृत्व में पंजाब में, सैयद हैदर रजा के नेतृत्व में दिल्ली में, मद्रास में चिदंबरम पिल्लई के नेतृत्व में इत्यादि।

स्वदेशी आंदोलन का भारत पर गहरा प्रभाव पड़ा, जिससे न केवल ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को बढ़ावा मिला, बल्कि स्वदेशी उद्योगों और राष्ट्रीय शिक्षा को भी प्रोत्साहन मिला। स्वदेशी आंदोलन ने भारतीय उद्योगों को बढ़ावा दिया, जिससे कपड़ा मिलें, साबुन और माचिस की फैक्टरियां, चमड़े के कारखाने, बैंक, बीमा कंपनियां और दुकानें स्थापित हुईं।

क्या यह अब हमारे लिए जरूरी नहीं है। स्वदेशी आंदोलन के परिणामस्वरूप, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई और बंगाल नेशनल कॉलेज और देश भर में कई राष्ट्रीय

स्कूल और कॉलेज खोले गए। स्वदेशी आंदोलन ने विदेशी वस्तुओं, विशेष रूप से कपड़ों, चीनी, नमक और विलासिता की वस्तुओं का बहिष्कार किया, जिससे उनकी बिक्री में कमी आई। क्या इस तरह के आंदोलन की आज जरूरत नहीं है? अमेरिकी बॉस की भारत को आर्थिक तौर पर नुकसान पहुंचाने वाली हरकतों के संदर्भ में प्रधानमंत्री द्वारा स्वदेशी का आह्वान यदि पूरे देश मे एक आंदोलन का रूप ले ले तो अमरीकी हितों को एक बड़ा झटका लगेगा, स्वदेशी हमारी दीर्घकालीन आर्थिक नीति का आवश्यक हिस्सा होना चाहिए, देश का नीति आयोग इस पर ध्यान दे। हमें स्वदेशी साधनों के उपयोग पर बल देना चाहिए।

आज के दौर में स्वदेशी और आत्मनिर्भरता की जरूरत फिर से महसूस होने लगी है। विकसित देश उन्हीं के होते हैं, जिनमें स्वदेशी उत्पादों का उत्पादन होता है। यदि हम दूसरे देशों पर निर्भर रहेंगे, तो वे हमें मजबूरी में ऊंचे दाम पर चीजें बेचेंगे और हमें उन्हें खरीदने की आवश्यकता होगी। स्वदेशी आंदोलन, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा, आज आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने का आधार बन चुका है।

यह आंदोलन न केवल आर्थिक स्वावलंबन को बढ़ावा देता है, बल्कि राष्ट्रीय गौरव और सांस्कृतिक पहचान को भी मजबूत करता है। हर भारतीय को स्वदेशी उत्पादों को अपनाने की जरूरत है, क्योंकि यह देश की अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने, रोजगार सृजन करने और वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति को मजबूत करने का मार्ग प्रशश्त करता है। स्वदेशी उत्पादों को अपनाने से न केवल विदेशी आयात पर निर्भरता कम होती है, बल्कि स्थानीय कारीगरों, किसानों और उद्यमियों को प्रोत्साहन मिलता है। यह आंदोलन भारत को एक मजबूत और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का संकल्प है।

हर भारतीय को इस आंदोलन का हिस्सा बनना चाहिए, क्योंकि स्वदेशी अपनाना केवल खरीददारी का निर्णय नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण का एक कदम है। भारतीय समाज का एक वर्ग स्वदेशी वशतुओं को गर्व और सांस्कृतिक पहचान से जोड़ता है तो दूसरी तरफ शहरी मध्यवर्ग और उच्चवर्ग के लिए आज भी विदेशी ब्रांड एक 'प्रतिष्ठा प्रतीक' बने हुए हैं जिससे स्वदेशी उत्पादों को विपणन और ब्रांडिंग के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है।

इसलिए सरकार सब कुछ करेगी, यह मानना गलत होगा। सभी भारतीयों को स्वदेशी आंदोलन से जुडऩा होगा और स्वदेशी को बल देना होगा। सरकार और उद्यमी को भी गुणवत्ता और नवाचार को स्वीकार करना होगा तथा छोटे उद्यमों को ऋण, प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता की व्यवस्था करनी होगी।

स्वदेशी उत्पादों की ब्रांड पहचान भी जरूरी रहेगी। भारत के पास अवसर हैं, लेकिन उसके लिए स्वदेशी जरूरी है। भारत के पास एक विशाल घरेलू बाजार है जो स्वदेशी उत्पादों की स्थिर मांग बन सकता है। सरकार और निजी क्षेत्र के सहयोग से स्वदेशी उद्योगों को वैश्विक शतर पर पहुंचाया जा सकता है और उसके लिए नवाचार और उद्यमशील युवा को बल और साथ मिलना जरूरी है।

आवश्यक है कि नीतियों का प्रभावी क्रियान्वयन, तकनीकी नवाचार में निवेश, और सामाजिक मानसिकता में बदलाव लाकर स्वदेशी को एक सशक्त और प्रतिस्पर्धी विकल्प बनाया जाए। यदि भारत 'ग्लोबल इन विजन, लोकल इन प्रैक्टिस' की नीति अपनाए, तो स्वदेशी आंदोलन 21वीं सदी में भारत को वैश्विक नेतृत्व की दिशा में अग्रसर कर सकता है। याद रहे कि विदेशी चीजों के इश्तेमाल से दुश्मन के हिमायती देशों की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और हर देशवासी को ऐसा नहीं करना है।

नैतिकता और सुशासन के भेष में शैतानियत भरा इरादा

अनिल जैन

आज अगर देश में यह धारणा होती कि संवैधानिक व्यवस्था सामान्य ढंग से काम कर रही है और कानून लागू करने वाली एजेंसियां निष्पक्षता से ठोस तथ्यों के आधार पर कदम उठाती है, तो प्रश्तावित नए कानून को एक स्वस्थ पहल माना जाता। दुर्भाग्य से आज धारणाएं उसके उलट हैं। जो धारणा व्यापक तौर पर प्रचलित है, वह यह कि कानून लागू करने वाली एजेंसियां राजनेताओं के दल और उनकी राजनीतिक प्रतिबद्धता को देखकर उनके अपराध तय करती हैं। ऐसे में प्रश्तावित कानून पर विपक्षी खेमों में और आम लोगों में भी आशंका पैदा होना स्वाभाविक है।

सुप्रीम कोर्ट ने इसी महीने की आठ तारीख (8 अगश्त) को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा था कि वह एक 'धूर्त' की तरह काम करने के बजाय कानून के दायरे में रह कर काम करे। इससे पहले 21 जुलाई, 2025 को भी शीर्ष अदालत के प्रधान न्यायाधीश बीआर गवई ने ईडी के बहाने केंद्र सरकार को नसीहत देते हुए कहा था कि, 'राजनीतिक लड़ाइयां अदालत में नहीं बल्कि जनता के बीच लड़ी जानी चाहिए।'

उससे भी पहले 6 मई, 2025 को शीर्ष अदालत ने दो टूक कहा था कि ईडी ने बिना सबूत के आरोप लगाने का 'पैटर्न' अपना लिया है। कोर्ट ने इस प्रवृत्ति पर चिंता जताते हुए कहा था कि कई मामलों में ईडी बिना पर्याप्त सबूतों के आरोप लगाती है। इसी साल फरवरी 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की कार्यप्रणाली को 'संवैधानिक प्रावधानों के प्रति असम्मान' करार देते हुए कहा था कि वह 'कानून के विपरीत दलीलें देने' को बर्दाशत नहीं करेगा।

इससे कुछ ही दिनों पहले 21 जनवरी, 2025 को उच्चतम न्यायालय ने ईडी की हिरासत प्रक्रिया को अवैध ठहराया था और इसे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करार देते हुए आरोपी को जमानत दे दी थी।

पिछले सात-आठ महीने के दौरान देश की सबसे बड़ी अदालत की ओर से की गई ये सभी टिप्पणियां इस आम धारणा को पुख्ता करती हैं कि ईडी की कार्रवाइयां राजनीतिक प्रतिशोध से प्रेरित होती हैं। केंद्र सरकार की ही एक अन्य एजेंसी केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई भी अपनी कार्यप्रणाली को लेकर सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न राज्यों के हाई कोर्ट से इसी तरह की सख्त टिप्पणियां अक्सर सुनती रहती हैं। इसके बावजूद अब केंद्र सरकार इन्हीं एजेंसियों को यह अधिकार देने वाला कानून बनाना चाहती है कि वे जब चाहे किसी भी निर्वाचित सरकार के मुख्यमंत्री या मंत्री का क्रियाकर्म कर दे। यह नए मिजाज का लोकतंत्र विकसित हो रहा है- पुलिसिया लोकतंत्र।

इस सिलसिले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नैतिकता और सुशासन का ढोल पीटते हुए संसद के मानसून सत्र के अंतिम चरण में 20 अगश्त को आनन-फानन में तीन विधेयक संसद में पेश किए, जो अगर पारित हो गए तो गंभीर आपराधिक मामलों में जेल जाने की स्थिति में प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और राज्यों के मंत्रियों को उनके पद से हटाने का प्रावधान हो जाएगा। हालांकि इस प्रश्तावित कानून के दायरे में प्रधानमंत्री को रखने का कोई मतलब नहीं है।

यह प्रावधान एक हास्यास्पद पाखंड है, क्योंकि सब जानते हैं कि भारत जैसे देश में जहां बैंक से ठगी करने वाले किसी रसूखदार कारोबारी या सत्तारूढ़ दल या उसके समर्थक किसी धार्मिक मठ से जुड़े किसी बलात्कारी के खिलाफ तक आसानी से एफआईआर दर्ज नहीं होती है, वहां किसकी हिम्मत होगी कि वह प्रधानमंत्री के खिलाफ किसी मामले में एफआईआर दर्ज कर उन्हें जेल भेज दे? ऐसा होना संभव ही नहीं है।

आज अगर देश में यह धारणा होती कि संवैधानिक व्यवस्था सामान्य ढंग से काम कर रही है और कानून लागू करने वाली एजेंसियां निष्पक्षता से ठोस तथ्यों के आधार पर कदम उठाती है, तो प्रश्तावित नए कानून को एक स्वस्थ पहल माना जाता। दुर्भाग्य से आज धारणाएं उसके उलट हैं। जो धारणा व्यापक तौर पर प्रचलित है, वह यह कि कानून लागू करने वाली एजेंसियां राजनेताओं के दल और उनकी राजनीतिक प्रतिबद्धता को देखकर उनके अपराध तय करती हैं। ऐसे में प्रश्तावित कानून पर विपक्षी खेमों में और आम लोगों में भी आशंका पैदा होना स्वाभाविक है।

चूंकि इस प्रश्तावित कानून पर केंद्र ने विपक्ष से कोई संवाद नहीं किया है और संसद का सत्र समाप्त होने से महज एक दिन पहले गृह मंत्री ने संसदीय नियमों और प्रक्रियाओं का पालन किए बगैर ये विधेयक पेश किए हैं, लिहाजा सरकार की नियत पर सवालों का उठना और प्रश्तावित कानून को नैतिकता और सुशासन के आवरण में सत्ता के केंद्रीयकरण की एक शैतानियत भरी खूंखार कोशिश के रूप में देखा जाना लाजिमी है।

गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया है कि ये विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भ्रष्टाचार विरोधी अभियान और राजनीति के शुद्धिकरण के संकल्प की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उनका यह दावा सरासर हास्यास्पद है, क्योंकि मोदी को और उनकी सरकार को अगर भ्रष्टाचार से वाकई परहेज होता तो वे इस पहलकदमी के लिए 11 साल का इंतजार नहीं करते। वे तो यह गर्जना करते हुए ही सत्ता में आए थे कि, ''न खाऊंगा और न खाने दूंगा''।

देश ने तो यही देखा है कि उनकी सरकार ने अरबों रुपये के घोटालों में फंसे हेमंत बिस्व सरमा, एकनाथ शिंदे, चंद्रबाबू नायडू, अजीत पवार, नारायण राणे, अशोक चह्वाण, एचडी कुमार स्वामी, सुवेंदु अधिकारी जैसे अनगिनत नेताओं के खिलाफ मामले सिर्फ इसलिए रफा-दफा कर दिए कि इन लोगों ने भाजपा में शामिल होना या सत्ता में उसका सहयोगी बनना कुबूल कर लिया। भाजपा के शिवराज सिंह और रमन सिंह जैसे कई नेताओं पर अरबों रुपये के भ्रष्टाचार के आरोप हैं लेकिन आज तक उनके खिलाफ कार्रवाई तो दूर, जांच तक नहीं हुई है।

नियमानुसार सदन में कोई भी विधेयक पेश होता है तो सदस्यों को उस विधेयक की प्रति 24 घंटे पहले उपलब्ध करानी होती है, ताकि वे विधेयक पर चर्चा के लिए तैयारी करके सदन में आएं, लेकिन ये विधेयक पेश हुए 20 अगश्त को सुबह और इन विधेयकों की प्रतियां सांसदों के पास भेजी गई 19 अगश्त की देर शाम को। लोकसभा सचिवालय को भी इन विधेयकों के बारे में 19 जनवरी की शाम को सूचित किया गया और इन विधेयकों को पेश करने के लिए विशेष अनुमति मांगी गई, जो कि मिलनी ही थी।

बहरहाल एक प्रश्ताव के जरिये इन विधेयकों को संसद की संयुक्त समिति के पास भेज दिया गया है, जो इन विधेयकों की समीक्षा कर अपनी रिपोर्ट संसद के शीतकालीन सत्र में पेश करेगी। हालांकि इसके बाद भी इन विधेयकों का पारित होना आसान नहीं है, क्योंकि इन्हें संसद में दो तिहाई बहुमत से पारित कराना होगा, जो कि मौजूदा स्थिति में बेहद मुश्किल है।

मोदी सरकार अभी सहयोगी दलों के समर्थन पर टिकी हुई है और लगता नहीं कि सारे सहयोगी दल खास कर तेलुगू देशम और जनता दल (यू) इन विधेयकों का समर्थन कर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा काम करेंगे, क्योंकि ये विधेयक कानून का रूप लेने के बाद न सिर्फ विपक्षी दलों के लिए तलवार बनेगा, बल्कि यह भाजपा के लिए अपने सहयोगी दलों को भी ब्लैकमेल करने का हथियार बन जाएगा।

फिर भी अगर किसी तरह सरकार संसद में इन विधेयकों को पारित करा लेती है तो उसके लिए अगली बड़ी चुनौती होगी कम से कम 15 राज्यों की विधानसभा में इन्हें पारित कराना, जो कि आसान नहीं लगता।

दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार इस समय चौतरफा मुसीबतों से घिरी हुई है। राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर मोदी सरकार ने लंबे समय से यह नैरेटिव बना रखा था कि वह इस मुददे पर कोई समझौता नहीं करती है, लेकिन पहलगाम कांड और ऑपरेशन सिंदूर से उस नैरेटिव की कलई उतर चुकी है।

पाकिश्तान पर बढ़त बना रही भारतीय सेना को उसने न सिर्फ अमेरिकी दबाव में सीजफायर करने के लिए मजबूर किया बल्कि इस सिलसिले में उसे अंतरराष्ट्रीय शतर पर भी कोई समर्थन नहीं मिला और उल्टे रणनीतिक रूप से पाकिश्तान की ताकतवर देशों के साथ नजदीकियां बढ़ गईं, जो कि कूटनीतिक मोर्चे पर भारत की बड़ी नाकामी है।

इधर घरेलू राजनीति में उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से इश्तीफा दिलवाने वाले प्रकरण ने तो मोदी सरकार को कमजोर किया ही, साथ ही उजागर हुई गंभीर चुनावी गड़बड़ियों और बिहार में अचानक शुरू हुए मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के कारण चुनाव आयोग के विवादों में घिर जाने की वजह से भी उसकी मुश्किलें बढ गई हैं। चुनावी गड़बड़ियों के उजागर होने और मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण जैसे विवादास्पद अभियान ने समूचे विपक्ष को एकजुट कर दिया है।

बिहार में इस अभियान का तीव्र विरोध हो रहा है, जो अन्य गैर भाजपा शासित राज्यों में भी फैलने की संभावना है।

इसलिए लगता है कि इन्हीं सब बातों से लोगों का और खास कर विपक्षी दलों का ध्यान हटाने के सरकार ने इन तीन नए कानूनों को लाने की नैतिकता में लिपटी अनैतिक पहल की है, जिसका हश्र तीन विवादास्पद कृषि कानूनों जैसा ही होने की संभावना है, जिन्हें प्रधानमंत्री मोदी ने भारी विरोध और लगभग 500 किसानों की दर्दनाक मौत के बाद यह कहते हुए वापस ले लिया था कि ''शायद मेरी तपस्या में ही कोई कमी रह गई है। ''

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं)

असम सरकार का 'शूट एट साइट' आदेश और हिंदू त्योहारों की सुरक्षा

डॉ. मयंक चतुर्वेदी

भय बिनु होइ न प्रीति। गोस्वामी तुलसीदास की यह चौपाई केवल अध्यात्म का संदेश नहीं, बल्कि शासन और व्यवस्था के लिए भी गहरी सीख है। यही कारण है कि असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने दुर्गा पूजा से ठीक पहले धुबरी जिले में शूट एट साइट का आदेश देकर स्पष्ट संकेत दिया कि अब त्योहारों की आड़ में साम्प्रदायिक हिंसा की कोई गुंजाइश नहीं बचेगी।

इस आदेश ने पूरे देश में हलचल मचा दी है, क्योंकि यह शायद पहली बार है जब किसी हिंदू पर्व की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इतनी कठोर व्यवस्था लागू की गई है। सवाल यह भी उठ रहा है कि आखिर असम सरकार को इतना बड़ा और अभूतपूर्व फैसला लेने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या यह आदेश केवल प्रशासनिक मजबूरी थी या फिर इसके पीछे एक व्यापक सामाजिक और राजनीतिक संदेश छुपा है? और सबसे अहम, क्या यह कदम वहां अल्पसंख्यक बन चुके हिंदुओं के लिए एक सुरक्षा कवच है?

धुबरी जिले की हकीकत इस आदेश की पृष्ठभूमि को समझने में मदद करती है। वर्ष 1951 में यहाँ हिंदू आबादी 43.5 प्रतिशत थी लेकिन समय के साथ यह घटती गई और 2011 की जनगणना तक केवल 19.92 प्रतिशत रह गई। वहीं, मुस्लिम आबादी 79.67 प्रतिशत तक पहुंच गई।

यानी जो इलाका कभी हिंदुओं का गढ़ माना जाता था, वहां अब वे अल्पसंख्यक बन चुके हैं। कई अध्ययनों के मुताबिक यह परिवर्तन केवल उच्च जन्मदर का परिणाम नहीं, बल्कि बांग्लादेश से निरंतर हो रही घुसपैठ का असर भी है। यही वजह है कि धुबरी अवैध प्रवासियों के खिलाफ अभियान का सबसे बड़ा केंद्र बन गया है।

यही नहीं, जून 2025 में धुबरी का एक हनुमान मंदिर उस समय सुर्खियों में आया जब उसमें अज्ञात लोगों ने पशु मांस के टुकड़े फेंक दिए। घटना के बाद बाजार बंद हो गया, पथराव हुआ और सांप्रदायिक तनाव भड़क उठा। इसके कुछ ही सप्ताह बाद अतिक्रमण हटाने गई सरकारी टीम पर भीड़ ने हमला कर दिया, जिसमें कई पुलिसकर्मी और अधिकारी घायल हुए। इन घटनाओं ने साफ कर दिया कि यह जिला बेहद संवेदनशील है और किसी भी धार्मिक अवसर पर यहाँ हालात बिगड़ सकते हैं। इसी संदर्भ में मुख्यमंत्री हिमंता सरमा ने शूट एट साइट का आदेश जारी किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह आदेश पूरे असम पर लागू नहीं है, बल्कि केवल धुबरी के लिए है। लेकिन संदेश पूरे राज्य और देश तक गया कि त्योहारों की शांति बिगाड़ने की कोशिश करने वालों को अब बख्शा नहीं जाएगा।

यह कदम उस व्यापक पैटर्न का हिस्सा है, जो पिछले कुछ वर्षों में देशभर में उभरता दिखाई दे रहा है। हिंदू त्योहारों पर हिंसा की

घटनाएँ लगातार सामने आ रही हैं। वर्ष 2022 में हनुमान जयंती और रामनवमी की शोभा यात्राओं के दौरान दंगे भड़के। 2023 में भी यही सिलसिला जारी रहा। 2024 की बात करें तो सरस्वती पूजा विसर्जन के दौरान सबसे ज्यादा हिंसक घटनाएँ हुईं। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद भी चार बड़ी हिंसक वारदातें दर्ज हुईं। गणेश उत्सव में भी चार बार तनाव की खबरें आईं और रामनवमी पर तीन बार दंगे हुए। सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोसायटी एंड सेक्युलरिज्म की रिपोर्ट बताती है कि 2024 में कुल 59 साम्प्रदायिक तनाव की घटनाएँ हुईं, जिनमें से 26 सीधे-सीधे त्योहारों से जुड़ी थीं। ताजा घटनाएँ इस पैटर्न को और पुख्ता करती हैं। गुजरात के वडोदरा में गणेशोत्सव की शोभायात्रा पर अंडे फेंके गए। उत्तर प्रदेश के बहराइच में गणपति की शोभायात्रा पर पटाखे फेंके गए। दोनों घटनाओं ने श्रद्धालुओं की भावनाएँ आहत कीं और तनाव पैदा किया। जब त्योहारों पर बार-बार इस तरह की हरकतें हों तो यह मानना कठिन नहीं कि इन्हें साजिशन अंजाम दिया जा रहा है।

अकादमिक शोध भी इस पैटर्न को समझाने की कोशिश करता है। आशुतोष वार्ष्णेय और स्टीवन विल्किंसन का अध्ययन बताता है कि जिन जिलों में मुस्लिम आबादी 20 प्रतिशत से अधिक होती है, वहां दंगे की संभावना तीन गुना बढ़ जाती है। साथ ही, जब हिंदू और मुस्लिम त्योहार एक ही दिन आते हैं, तो हिंसा की आशंका और बढ़ जाती है। भारत के 110 जिलों में मुस्लिम आबादी 20 प्रतिशत से ज्यादा है।

यानी ये इलाके स्वाभाविक रूप से संवेदनशील हो जाते हैं। धुबरी तो इस परिभाषा में और भी गहराई से फिट बैठता है, जहाँ हिंदुओं की संख्या लगातार घट रही है और वे अपनी धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर असुरक्षित महसूस करने लगे हैं।

वस्तुतः यही पृष्ठभूमि बताती है कि मुख्यमंत्री हिमंता सरमा का फैसला केवल कानून-व्यवस्था का उपाय नहीं, बल्कि धुबरी के हिंदुओं को मनोवैज्ञानिक आश्वासन देने वाला कदम भी है। यह आदेश अल्पसंख्यक हिंदुओं को संदेश देता है कि राज्य सरकार उनके पर्वों और आस्था की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएगी, चाहे वह कितना भी कठोर क्यों न हो। विपक्ष इस आदेश को सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का प्रयास बता रहा है। कुछ मुस्लिम संगठनों ने इसे धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला कहकर विरोध जताया है। किंतु यह भी एक हकीकत है कि धुबरी जैसे जिलों में अगर हिंदू त्योहारों पर बार-बार हिंसा होती रहे और सरकार सिर्फ अपील करती रह जाए, तो इससे हिंदुओं के भीतर गहरी निराशा और भय पैदा होगा। ऐसे हालात में कठोर कदम ही विश्वास बहाल कर सकता है।

सवाल बरकरार है कि क्या अब हिंदुओं को हर त्योहार सुरक्षा के साये में ही मनाना पड़ेगा? क्या दुर्गा पूजा, रामनवमी और गणेशोत्सव अब केवल पुलिस बैरिकेड और सुरक्षा बलों की मौजूदगी में ही सुरक्षित रहेंगे? यह स्थिति न केवल त्योहारों की खुशी को कम करती है, बल्कि यह सामाजिक ताने-बाने की गहरी टूटन को भी दर्शाती है।

अब फैसले की आलोचना हो या समर्थन, एक तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि असम का यह आदेश धुबरी जैसे संवेदनशील जिलों में अल्पसंख्यक हिंदुओं के लिए सुरक्षा की ढाल है। यह केवल कानून-व्यवस्था का उपाय नहीं, बल्कि यह विश्वास दिलाने वाला संदेश है कि राज्य सरकार उनके साथ है। अगर समाज में दंगों का वायरस फैलने लगे, तो उसे रोकने के लिए कठोर दवा ही काम आती है।

कहना होगा कि सही अर्थों में व्यवहारिक धरातल पर मुख्यमंत्री हिमंता सरमा का यह निर्णय हिंदुओं की सुरक्षा और आस्था को संरक्षण देने वाला है। यह फैसला अभूतपूर्व है, लेकिन धुबरी जैसे हालात भी अभूतपूर्व हैं। ऐसे में यह आदेश केवल एक प्रशासनिक कदम नहीं, बल्कि धुबरी के अल्पसंख्यक हिंदुओं के लिए भरोसे की गारंटी है।

मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यहां यह संदेश भी देना चाहते हैं कि राज्य में कानून-व्यवस्था के साथ खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

फिर भी, व्यावहारिक श्तर पर इसका सबसे बड़ा लाभ धुबरी जैसे जिलों के हिंदू परिवारों को मिलने वाला है। उम्मीद करें कि वे अब अपने पर्व-त्योहार मनाने में भय महसूस नहीं करेंगे और यही इस आदेश की असली सफलता होगी।

स्वामी, मुद्रक व प्रकाशक श्रीमती आशा शर्मा द्वारा 707 मंदाकिनी टावर सेक्टर -4, वैशाली गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) भारत से प्रकाशित एवं एन.सी.आर. प्रिंटर्स, 15/19 साइट-4, साहिबाबाद इंडस्ट्रीयल एरिया जनपद गाजियाबाद से मुद्रित। संपादक : संजय शर्मा
फोन: 9899683800 वेबसाइट : www.khabariya.com ई-मेल: todayncr@gmail.com >> ncrtoday@hotmail.com RNI-UPHIN/2009/30721

संक्षिप्त समाचार

कॉलोनाइजर हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई, शूटरों को असलहा सप्लाई करने का मुख्य आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार

वाराणसी, एजेंसी। वाराणसी जिले के सारनाथ के सिंहपुर में कॉलोनाइजर महेंद्र गौतम की हत्या में शामिल मुख्य आरोपी मुकीम को पुलिस ने फरीदपुर में मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। मुकीम ने ही बदमाशों को असलहा सप्लाई किया था। अन्य आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। डीसीपी वरुणा प्रमोद कुमार ने बताया की कालोनाइजर महेंद्र गौतम की हत्या की साजिश मुख्य आरोपी मुकीम ने ही रची थी। शूटरों को असलहा सप्लाई किया था। तफ्तीश में जुटी टीम को सूचना मिली कि फरीदपुर में मुख्य आरोपी मुकीम शूटरों को रुपये की लेनदेन के लिए बुलाया है। एसओजी की टीम ने घेराबंदी की तो मुकीम ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में मुकीम के पैर में गोली लगी है। अन्य आरोपियों से पूछताछ की जा रही है।

सात कर्मचारी मिले अनुपस्थित, रोका वेतन

बलरामपुर, एजेंसी। स्वास्थ्य सुविधाओं की पड़ताल करने के लिए मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. मुकेश कुमार रस्तोगी ने मंगलवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तुलसीपुर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सात कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। सभी का वेतन रोकते हुए स्पष्टीकरण मांगा गया है। सीएमओ ने सीएचसी के इमरजेंसी वार्ड, ओपीडी, लैब व प्रसव कक्ष का निरीक्षण कर संसाधनों के बारे में जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान सुरक्षा गार्ड विजय कुमार, दुलारी देवी, मीरा देवी, ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधक प्रियंका गुप्ता, बीसीपीएम अमरेंद्र सिंह, ब्लॉक लेखा प्रबंधक लालबाबू मौर्य एवं एलएचवी सुदेश अनुपस्थित पाए गए। सीएमओ ने नाराजगी जताते हुए सभी का वेतन रोक दिया गया। नोटिस देकर तीन दिन के अंदर स्पष्टीकरण मांगा है। सीएमओ ने अधीक्षक को साफ-सफाई कराने व कीटनाशक का छिड़काव कराने का निर्देश दिया। अधिकांश स्वास्थ्य कर्मियों को निर्धारित ड्रेस कोड में न मिलने पर भी फटकार लगाई। सीएमओ ने तुलसीपुर में संचालित जनपदीय ड्रग वेयर हाउस का भी निरीक्षण किया। इस अवसर पर जिला मलेरिया अधिकारी राजेश पांडेय, अधीक्षक डॉ. विकल्प मिश्र व डॉ. आलोक चौधरी मौजूद रहे।

आभूषण व्यवसायी से लूट का आरोपी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार, पैर में लगी गोली

प्रयागराज, एजेंसी। फूलपुर में आभूषण कारोबारी को तमंचा सटाकर ढाई लाख रुपये से अधिक के जेवरात लूटने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फूलपुर थाना क्षेत्र के लिलहट नहर के पास हुई मुठभेड़ में आरोपी पुलिस की गोली से घायल हो गया। उसके अन्य साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे। गिरफ्तार बदमाश के पास पुलिस को एक किलो चांदी का आभूषण बरामद हुआ है। फूलपुर कोतवाली क्षेत्र के वरुण बाजार निवासी शिव शंकर सोनी (28) पुत्र स्वर्गीय रामबाबू ने फूलपुर के भोगवारा बाजार में ज्वेलरी की दुकान खोल रखी है। रविवार शाम को दुकान बंद कर वह वापस घर लौट रहा था। जैसे ही भोगवारा से वरुणा बाजार जाने वाले मार्ग पर खोजापुर गांव के सामने पहुंचा तभी दो बाइकों पर सवार पांच बदमाशों उन्हें ओवरटेक कर रोक लिया। इसके बाद वह तमंचा सटाकर व्यवसायी से मारपीट करने लगे। जिससे वह घायल हो गया। इसके बाद बदमाशों ने बाइक की डिक्की तोड़कर करीब दो लाख के गहने और 15 हजार नकद छीन लिए और फरार हो गए थे। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। हालांकि एसीपी फूलपुर पंकज लवानिया का कहना था कि प्रथम दृष्टया घटना लूट की नहीं बल्कि टप्पेबाजी की प्रतीत हो रही है। इसमें तीन संदिग्धों की तलाश की जा रही है।

बाढ़ से कितना हुआ नुकसान बताएगा सेटलाइट

इसी मानसून सीजन में होगा ट्रायल, पौने तीन करोड़ किसानों को फायदा

लखनऊ, एजेंसी। उत्तर प्रदेश में बाढ़ से नुकसान के आकलन में राजस्व कर्मियों की मनमानी खत्म होगी। इसका आकलन सेटेलाइट के माध्यम से होगा। इसरो की मदद से इसी मानसून सीजन में ट्रायल की तैयारी चल रही है। इस योजना के लाभ के दायरे में यूपी के करीब पौने तीन करोड़ से ज्यादा किसान आएंगे।

प्रदेश में हर साल करीब 43 जिले बाढ़ से प्रभावित रहते हैं। इस वर्ष भी अब तक इन जिलों की 116 तहसीलों के 2600 से ज्यादा गांव प्रभावित हैं। 1594 गांवों की खेती प्रभावित है। अभी नुकसान का आकलन राजस्व कर्मी भौतिक रूप से करते हैं। इसमें प्राय~ न सिर्फ देरी की, बल्कि गलत सर्वे की भी शिकायत आती है।

इस समस्या से निजात के लिए इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनाइजेशन (इसरो) के नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर (एनआरएससी) और रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर (आरएसएसी) की डाटा ऑब्जर्वेशन सेवाओं की मदद ली जाएगी।

उच्चपदस्थ सूत्रों के मुताबिक, प्रदेश में कृषि भूमि के 85 प्रतिशत गाटा संख्या के डाटा की ऑनलाइन मैपिंग हो चुकी है। इसलिए सेटेलाइट के माध्यम से सर्वे में कोई समस्या भी नहीं रह गई है। सेटेलाइट किसी भी क्षेत्र में सप्ताह भर के अंतर पर दो बार कृषि भूमि के लाइव चित्र लेकर भेजेगा। अगर दोनों बार के डाटा में खेतों में जलभराव आएगा तो इसका मतलब है कि फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। यहां बता दें कि अगर किसी खेत में सप्ताह भर पानी भरा रहता है तो फसल की गुणवत्ता और मात्रा पर काफी असर पड़ता है।

पहली बार एक ही सीजन में दो बार आई बाढ़, दूसरी बार चेतावनी बिंदु के पार हुईं गंगा

वाराणसी। गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी का सिलसिला लगातार तीसरे दिन जारी रहा। 24 घंटे में गंगा के जलस्तर में 1.99 मीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बाढ़ के कारण निचले इलाकों में दोपहर से ही पलायन भी शुरू हो गया। नदी विज्ञानियों का कहना है कि यह पहला मौका है जब एक ही सीजन में दूसरी बार बाढ़ आई है। बाढ़ की वजह से 32 परिवार के 133 लोगों ने घर छोड़ दिया है। बाढ़ से दो मोहल्ले और एक तहसील प्रभावित हैं। गंगा के जलस्तर में हर घंटे सात सेंटीमीटर की रफ्तार से बढ़ोतरी हो रही है। बुधवार को गंगा चेतावनी बिंदु दूसरी बार पार कर गई। ऐसे में सुबह 10 बजे गंगा का जलस्तर 70.42 मीटर तक पहुंच गया। जो चेतावनी बिंदु से 16 सेंटीमीटर ऊपर है। केंद्रीय जल आयोग की ओर से जारी बाढ़ बुलेटिन के अनुसार मंगलवार को सुबह आठ बजे गंगा का जलस्तर 68.94 मीटर दर्ज किया गया। जलस्तर में नौ सेंटीमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से बढ़ोतरी हो रही थी। शाम चार बजे जलस्तर 69.52 मीटर तक पहुंच गया और इसमें छह सेंटीमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से बढ़ोतरी दर्ज की गई। शाम छह बजे जलस्तर 69.64 मीटर था। वहीं, रात नौ बजे जलस्तर में सात सेंटीमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से बढ़ोतरी हुई और जलस्तर 69.85 मीटर पहुंच गया। सोमवार की रात नौ बजे जलस्तर 67.86 मीटर पर था।

समस्या: अमेरिकी टैरिफ के धमाके से शहर के उद्योगों को 1500 करोड़ की चोट, कारोबारी बोले- निर्यात ऑर्डर रोके

कानपुर, एजेंसी। कानपुर में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से भारत पर लगाया गया 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ बुधवार सुबह से प्रभावी हो जाएगा। साथ ही अब वहां उत्पादों के निर्यात पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगेगा। पूर्व में 25 प्रतिशत टैरिफ लगाया जा चुका है। टैरिफ का प्रभाव शहर के चमड़ा, टेक्सटाइल और मशीनरी उद्योग पर खासा पड़ा है। 40 दिन के भीतर ही 1500 करोड़ के निर्यात आर्डर रोक दिए गए हैं। निर्यात रुकने से उत्पादन पर प्रभाव पड़ा है।

इकाइयों में अब एक या दो शिफ्ट में ही काम किया जा रहा है। जहां दो शिफ्ट में काम होता था वहां पर एक और जहां पर तीन शिफ्ट में काम होता था वहां दो शिफ्ट में ही काम हो रहा है। केवल अमेरिकी खरीदारों पर निर्भर निर्यातकों के सामने चुनौती ज्यादा बड़ी हो गई है। ऐसे में दैनिक श्रमिकों पर आने वाले समय में असर दिख सकता है। टैरिफ लगने से पूर्व अमेरिका में कानपुर समेत भारत से जाने वाले चमड़ा और चमड़ा से जुड़े उत्पादों पर अलग-अलग 6-11 तक का शुल्क लगता था।

टेक्सटाइल उद्योग पर खासा असर : अब 50 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ को जोड़ लें] तो 28 अगस्त के बाद भेजे जाने वाले उत्पाद पर 56-61 प्रतिशत का शुल्क लगेगा। हालांकि अब अमेरिकी खरीदारों से कारोबारी गतिविधियां वर्तमान में शून्य हो गई हैं। जो पुराने ऑर्डर भी थे उन्हें निरस्त कर दिया गया है। इसके अलावा टेक्सटाइल पर 63 प्रतिशत कुल शुल्क हो गया है। इससे टेक्सटाइल उद्योग पर खासा असर पड़ रहा है। अमेरिकी से टेक्सटाइल फैब्रिक्स आता था।

घरेलू बाजार में बनाएंगे और पैठ : चर्म निर्यात परिषद के क्षेत्रीय अध्यक्ष असद इराकी का कहना है कि परिषद के पदाधिकारियों की बैठक मंगलवार को की गई। इसमें अमेरिकी टैरिफ संकट पर चर्चा की गई। तय हुआ कि घरेलू बाजार में उत्पादों की बिक्री पर जोर रहेगा। इसके अलासा रूस, वाना रीजन, अफ्रीकी देशों के साथ कारोबारी रिश्ते बढ़ाए जाएंगे ताकि टैरिफ प्रभाव को कम किया जा सके।

आपूर्ति श्रृंखला होगी प्रभावित : उत्पादन में कमी आने से चमड़ा, टेक्सटाइल, मशीनरी उत्पादों की आपूर्ति श्रृंखला में बड़ा प्रभाव पड़ेगा। चमड़ा उद्योग में अलग-अलग प्रकार के केमिकलों का उपयोग होता है। इसका सालाना कारोबार 500-800 करोड़ का है। इसके अलावा फुटवियर के सोल, फीता, शू अपर, बक्क्ल और इससे जुड़े उत्पादों पर असर दिखेगा।

सात साल तक मैं उसकी पत्नी बनकर रहा, अब कहीं और कर रहा शादी, समलैंगिक संबंधों का खौफनाक अंजाम

मेरठ, एजेंसी। परीक्षितगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव में दोस्त की शादी तय होने पर युवक ने जहरीला पदार्थ खा लिया। आरोप है कि दोस्त ने शादी का वादा कर सात साल तक उसके साथ समलैंगिक संबंध बनाए। उसे सरकारी अफसर बनाने का भी वादा किया था। यह बात युवक ने डायरी में लिखी है। परिजनों ने आरोपी पर पुत्र को ब्लैकमेल कर संबंध बनाने और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाते हुए थाने में तहरीर दी है। दोनों युवक अलग-अलग समुदाय के हैं।

जहरीला पदार्थ खाने से पहले युवक ने डायरी में लिखा कि 2019 में वह गांव में अपने दोस्त के साथ उसके घर खेल रहा था। तभी दोस्त का मामा काम से लौटा। उसने अपने भांजे को दुकान पर भेज दिया। इसके बाद उसे उठाकर कमरे में ले गया। आरोपी ने उससे कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूं और तुमसे शादी करूंगा। इसके बाद उसके साथ समलैंगिक संबंध बनाए। आरोपी ने उसे सरकारी अफसर बनाने का भी वादा किया था। इसके बाद अक्सर उसके साथ संबंध बनाता रहा। आरोपी जहां बुलाता था, वह जाता रहा। दोनों के परिवारों के बीच किसी बात को लेकर लड़ाई भी हुई लेकिन उन्होंने एक-दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। कहता था कि तुम मेरी वाइफ हो। अब वह सब वादों से मुकर गया। उसने मेरे साथ विश्वासघात किया है। उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मेरी मौत का कारण आरोपी होगा।

उधर, युवक के पिता ने थाने में दी तहरीर में बताया कि गांव का ही युवक उनके बेटे को सात साल तक ब्लैकमेल कर संबंध बनाता रहा। आरोपी नोएडा में किराए के मकान में रहता है। उनके पुत्र को अपने कमरे पर बुलाकर रात में अपने पास रखता था। आरोपी से परेशान होकर 23 अगस्त को उनके पुत्र ने जहरीला पदार्थ खा लिया।

बुलंदशहर हादसा: गहरी नीद में धमाका... खून से सनी लाशों का ढेर

कासगंज, एजेंसी। कासगंज में रविवार की देर शाम रफातपुर गांव से जाहरवीर बाबा की जात के लिए डबल डेकर ट्रैक्टर ट्रॉली से श्रद्धालु निकले। आस्था और भक्ति के साथ श्रद्धालुओं ने गांव से यात्रा शुरू की। भजन कीर्तन करते हुए श्रद्धालुओं की ट्रैक्टर ट्रॉली गंतव्य की ओर बढ़ती जा रही थी। रात 12 बजे के बाद ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार ज्यादातर श्रद्धालु नींद के आगोश में आ गए। महिलाएं व बच्चे ज्यादातर ट्रॉली में ही बैठे थे जबकि ट्रॉली की दूसरी मंजिल पर युवा व अन्य ग्रामीण बैठे थे। खुर्जा के इलाके में अचानक कंटेनर ने पीछे से टक्कर मारी और ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार श्रद्धालु हादसे का शिकार हो गए। इस हादसे में 11 जानें चली गईं और 58 श्रद्धालु घायल हो गए।

रविवार की रात ट्रैक्टर ट्रॉली हादसे में घायल हुए लोग जान बचने के बाद भी हादसे से उभर नहीं पा रहे उनके मन में हादसे का खौफ है और आंखों में हादसे की खौफनाक तस्वीरें बसी हुई हैं जो उन्हें बेचैन कर रही हैं। उन्हें नींद भी नहीं आ रही। बार बार मन में तरह तरह के सवाल घुमड़ रहे हैं। हादसे के सभी घायलों का ऐसा ही आलम है।

हादसे में घायल हुईं धनदेवी मंगलवार को भी सहमी नजर आईं। उन्होंने बताया कि वह हादसे के वक्त नींद की झपकी में थीं। जब हादसा हुआ तो जोरदार धमाके जैसी आवाज हुई। ट्रैक्टर ट्रॉली सड़क पर घिसट रही थी। चीख पुकार मचने लगी। उनके हाथ पैर भी नहीं उठ रहे थे हालत बेहोशी जैसी हो गई, लेकिन चीखपुकार की आवाज कानों में गूंज रही थी। धनदेवी बतातीं हैं कि यह मंजर उन्हें सोने नहीं दे रहा। अजीब से बेचैनी बनी हुई है।

एक अन्य घायल जशोदा ने बताया कि घटना के समय वह सो रहीं थीं। हादसे के दौरान तेज आवाज हुई और वह बेहोश हो गईं। जब उन्हें होश आया तो उनके देवर राजीव ने उन्हें निकाला और पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया। जशोदा के चोटें आई हैं। हादसे का खौफ उन्हें परेशान कर रहा है। घायल हरी सिंह ने बताया कि वह सो रहे थे टक्कर होते ही आवाज सुनी, लेकिन फिर बेहोशी में चले गए। जब होश आया तो अस्पताल में भर्ती थे।

हादसे में घायल हुईं शकुंतला देवी अपने पति के साथ जात करने गईं थीं, लेकिन हादसे में उनके हाथ, पैर व शरीर में काफी चोटें आ गईं। शकुंतला देवी अभी भी हादसे को याद कर भावुक हो रहीं थीं और बोलने में भी दिक्कत हो रही थी। यही हाल ऊषा देवी ने बताया। ऊषा की छाती व पैर में गंभीर चोटें हैं और वह अभी भी हादसे से नहीं उबर पाई है। बार बार हादसे का मंजर उनकी आंखों में तैर रहा है।वहीं हादसे के चश्मदीद राजीव ने बताया कि हादसा इतना भयावह था कि हमेशा वह परेशान करेगा। वह बताते हैं कि परिवार के नौ लोग गए थे। जिनमें भाई योगेश की मौत हो गई जबकि परिवार के अन्य लोग घायल हो गए। उन्होंने बताया कि हादसे के बाद ट्रॉली घिसटती चली गई। चीखपुकार के अलावा कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। इसके बाद सभी को अस्पतालों में पुलिस व अन्य लोगों की मदद से भेजा गया। ऐसी आपदा गांव के लोगों ने कभी नहीं देखी। हमेशा इस दुर्घटना का दंश पीड़ित परिवारों व गांव वालों को परेशान करेगा।

अस्पताल संचालकों के लिए नए आदेश...अब बेसमेंट में नहीं चलेगी ओटी और आईसीयू, मरीज मिलने पर होगी कार्रवाई

आगरा, एजेंसी। उत्तर प्रदेश के आगरा में अब बेसमेंट में कोई अस्पताल संचालित नहीं होगा। ऑपरेशन थियेटर (ओटी), आईसीयू और वार्ड का भी संचालन नहीं होगा। बेसमेंट में मरीज भर्ती मिलने पर चिकित्सक और अस्पताल के विरुद्ध कार्रवाई होगी। यह आदेश मंगलवार को जिलाधिकारी अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने कलेक्ट्रेट में आयोजित पीसीपीएनडीटी जिला सलाहकार समिति की बैठक में दिए।

डीएम ने सीएमओ डॉ. अरुण श्रीवास्तव को बेसमेंट में संचालित अस्पताल, क्लीनिक, डे-केयर सेंटर की जांच के निर्देश दिए हैं। 15 दिन में सीएमओ को सर्वे रिपोर्ट देनी होगी। जिले में करीब 1300 चिकित्सा संस्थान 2024 में पंजीकृत थे। 2025-26 के लिए पंजीकरण चल रहे हैं। अभी तक करीब 700 चिकित्स संस्थान सीएमओ कार्यालय में पंजीकृत हुए हैं।

मंगलवार को डीएम ने अवैध अल्ट्रासाउंड सेंटर्स की जांच, मुखबिर के माध्यम से लिंग परीक्षण करने वालों को चिह्नित कराने और अल्ट्रासाउंड सेंटर्स पर चिकित्सक की बायोमेट्रिक हाजिरी अनिवार्य करने के निर्देश दिए। बैठक में तीन नए अल्ट्रासाउंड सेंटर के आवेदन स्वीकृत हुए, जबकि आठ अल्ट्रासाउंड सेंटरों के नवीनीकरण की संस्तुति की गई।

डीएम ने बेसमेंट में संचालित अस्पतालों के अलावा अल्ट्रासाउंड सेंटर्स की जांच के लिए अपर नगर मजिस्ट्रेट व पीसीपीएनडीटी ((गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम) के नोडल अधिकारी की टीम बनाई है। टीम सेंटर की जियो टैगिंग करेगी। फोटोग्राफी सहित रिपोर्ट देगी। सीएमओ डॉ.अरुण श्रीवास्तव ने बताया कि शहर में करीब 300 अल्ट्रासाउंड सेंटर हैं, जिनकी मशीनों से लेकर चिकित्सक की जांच कर रिपोर्ट डीएम को भेजी जाएगी।

निरस्त सेंटर में सील मशीनों की होगी जांच

जिन अल्ट्रासाउंड सेंटर्स के आवेदन निरस्त हो चुके हैं, उनकी मशीनें भी सील हैं। डीएम ने ऐसी सभी मशीनों की जांच के निर्देश दिए हैं। सीएमओ डॉ. अरुण श्रीवास्तव ने बताया कि पिछले एक साल में अवैध अस्पताल संचालकों के विरुद्ध केस दर्ज कराया है। 50 से अधिक अस्पतालों की जांच की गई है।

घर में घुसकर लाखों की नकदी व गहने ले गए बदमाश

अलीगढ़, एजेंसी। कोतवाली क्षेत्र के हाथरस-सिकंदराराऊ रोड स्थित गांव सूआ मोहनपुर में मंगलवार की दोपहर को बदमाश एक घर में घुसकर लाखों रुपये कीमत के सोने-चांदी के गहने और नकदी चोरी कर ले गए। घर पर महिला ने शोर मचाया तो बदमाश फरार हो गए। रतन सिंह उर्फ बंटू सिंह गांव के बाहर प्राथमिक विद्यालय के सामने कृषि क्षेत्र के इलाके में मकान बनाकर रहते हैं। रतन सिंह स्वयं नेशनल हाइवे की निर्माणदायी संस्था के वाहन का संचालन करने के लिए घर से बाहर रहते हैं। मंगलवार को रतन सिंह की पत्नी पुष्पा देवी अपनी पुत्रवधू प्रिया को घर पर अकेला छोड़कर अपने नाती के साथ अपने मायके के लिए चली गईं थीं।

रतन सिंह के दोनों पुत्र विक्की व विजय गाजियाबाद स्थित एक प्राइवेट कंपनी में कार्य करते हैं। पुत्रवधू प्रिया ने बताया कि वह घर पर अकेली थी। दोपहर को प्यास लगने पर वह पानी पीने के लिए एक गिलास लेने के लिए अंदर गई, तभी घर के आंगन में उसे कुछ अज्ञात व्यक्ति दिखाई दिए, जिन्हें देखकर वह उल्टे पैर ही बिना गिलास लिए ही वापस घर से बाहर आई और घर में चोर होने का शोर मचा दिया। प्रिया का शोर सुनकर ग्रामीण मौके की तरफ दौड़ पड़े। ग्रामीणों ने घर में अंदर घुसकर देखा तो अज्ञात बदमाश लाखों रुपये कीमत का सामान, नकदी और गहने लेकर फरार हो चुके थे। 10 दिन पहले भी अज्ञात बदमाशों ने पड़ोस के ही गांव सूआ में वीरेंद्र के घर में घुसकर चोरी की घटना को अंजाम दिया था। कस्बा के बाजार में भी दो दुकानों में चोरी का प्रयास किया जा चुका है।

बोगस फर्म बनाई...गार्ड का पैन इस्तेमाल कर की गई गड़बड़ी, एक फरवरी को मिला पंजीकरण, चार को हो गई बंद

कानपुर, एजेंसी। कानपुर के काकादेव कोचिंग में गार्ड के रूप में काम करने वाले ओमजी शुक्ला को दिल्ली के सीजीएसटी विभाग की ओर से मिले तीन करोड़ से अधिक के टैक्स का नोटिस देने के मामले में नया खुलासा हुआ है। पता चला है कि पंजीकरण मिलने के तीन दिन बाद खुद संचालक ने फर्म बंद करवा दी। तीन करोड़ से ज्यादा की आईटीसी का दावा भी किया गया। फर्म ने केवल एक अन्य फर्म के साथ एक साल में ही 17 करोड़ से ज्यादा के कपड़ों की खरीद-फरोख्त की। माना जा रहा है कि बोगस फर्म बनाकर और पीड़ित का पैन इस्तेमाल करके गड़बड़ी की गई।

उन्हें नोटिस देने से पहले विभाग ने दिल्ली स्थित फर्म के बैंक खातों की जानकारी के लिए संबंधित निजी बैंक से पत्राचार किया था। हंसपुरम में किराये के मकान में रहने वाले ओमजी को 21 अगस्त को विभाग की ओर से नोटिस भेजा गया था, जो 32 पेज का था। तीन करोड़ 14 लाख से ज्यादा का नोटिस दिया गया था। इस नोटिस से पहले उन्हें एक पेज का समन भेजा गया था। ओमजी ने बताया कि वह कभी भी दिल्ली नहीं गए। जब नोटिस आया तो कुछ समझ में नहीं आया। उनका बैंक खाता न्यूनतम बैलेंस के कारण बंद है। सैलरी मां सुषमा शुक्ला के खाते में आती थी।

सीए बोले- नोटिस का जवाब देंगे : पैन कार्ड कभी किसी को नहीं दिया। सात महीने से वह गार्ड का काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि नोटिस की जानकारी भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष ज्ञानेश मिश्रा को दी तो उनके साथ सोमवार को सीजीएसटी कानपुर कार्यालय के कमिश्नर से मुलाकात की। कमिश्नर ने कहा था कि जहां से भी नोटिस आया है उसका जवाब जरूर दें। अपनी स्थिति के बारे में जानकारी दें और विभागीय अफसरों से जांच कराने के लिए कहें। ज्ञानेश के साथ गार्ड ने मंगलवार को वरिष्ठ सीए धर्मेंद्र श्रीवास्तव से मुलाकात की। धर्मेंद्र कहा कि वह नोटिस का जवाब देंगे। उन्हें सीए ने मदद का भरोसा दिलाया।

भारत की 17 साल की कोयल बार का जलवा

अहमदाबाद, एजेंसी। 17 साल की कोयल ने गजब का जज्बा दिखाते हुए तब सुर्खियां बटोरीं, जब बिंदियारानी और मुथुरमुथुपंडी राजा जैसे भारोत्तोलक पदक जीतने में सफल रहे। कोयल को आने वाले समय का स्टार माना जा रहा है। 17 साल की भारतीय भारोत्तोलक कोयल बार ने मंगलवार को यहां राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप में महिलाओं की 53 किग्रा स्पर्धा में दो नए युवा विश्व रिकॉर्ड स्थापित करके युवा और जूनियर दोनों खिताब जीते। जूनियर और युवा दोनों वर्ग में प्रतिस्पर्धा करते हुए इस किशोरी ने कुल 192 किग्रा (85 किग्रा + 107 किग्रा) वजन उठाया। उन्होंने पहले 85 किग्रा भार उठाकर युवा स्नैच विश्व रिकॉर्ड की बराबरी की और फिर क्लीन एंड जर्क में अपने दूसरे प्रयास में 107 किग्रा भार उठाकर 105 किग्रा के रिकॉर्ड को बेहतर बनाया। इसके साथ ही, उन्होंने 188 किग्रा के मौजूदा युवा विश्व कुल रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया।

कोयल का प्रयास स्नेहा से बेहतर

कोयल का प्रयास उनकी हमवतन स्नेहा सोरेन से तीन बेहतर था, जिन्होंने 185 किग्रा (81 किग्रा + 104 किग्रा) के साथ सीनियर वर्ग में रजत पदक जीता था। इससे पहले महिलाओं में भारत की बिंदियारानी देवी और पुरुषों में मुथुपंडी राजा ने मंगलवार को अहमदाबाद में राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में रजत पदक जीतकर शानदार प्रदर्शन किया। हालांकि, सारी सुर्खियां गजब का जज्बा दिखाने वाली 17 वर्षीय कोयल ने बटोरीं।

बिंदियारानी को मिला पदक

महिलाओं के 58 किग्रा वर्ग में भाग लेने वाली बिंदियारानी ने 206 किग्रा (91 किग्रा स्नैच + 115 किग्रा क्लीन एंड जर्क) भार उठाकर रजत पदक जीता।

उन्होंने स्नैच में 85 किग्रा, 88 किग्रा और 91 किग्रा भार उठाया और क्लीन एंड जर्क में 110 किग्रा और 115 किग्रा भार उठाया। वह अपने अंतिम 122 किग्रा प्रयास में असफल रहीं और दूसरे स्थान पर रहीं, जबकि ऑस्ट्रेलिया की कियाना इलियट ने 212 किग्रा (100 किग्रा + 112 किग्रा) के साथ स्वर्ण पदक जीता। बिंदियारानी बर्मिंघम में 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में 55 किग्रा वर्ग में रजत पदक विजेता हैं। वह पूर्व राष्ट्रमंडल चैंपियन भी हैं, जिन्होंने 2019 में स्वर्ण और 2021 संस्करणों में रजत पदक जीता है।

मुथुपंडी ने भी जीता पदक

पुरुष वर्ग की बात करें तो, मुथुपंडी राजा 65 किग्रा भार वर्ग में स्वर्ण पदक के बेहद करीब पहुंच गए, लेकिन 296 किग्रा (128 किग्रा+168 किग्रा) वजन उठाकर स्वर्ण पदक जीतने से चूक गए। मलयेशिया के मुहम्मद अजनिल बिन बिदिन ने 297 किग्रा (125 किग्रा+172 किग्रा) वजन उठाकर स्वर्ण पदक जीता। पापुआ न्यू गिनी के मोरिया बारू 292 किग्रा (127 किग्रा+165 किग्रा) वजन उठाकर कांस्य पदक जीतने में सफल रहे।

300 से ज्यादा एथलीट्स

टूर्नामेंट के 30वें संस्करण में 31 देशों के 300 से ज्यादा भारोत्तोलक हिस्सा ले रहे हैं। टोक्यो 2020 की रजत पदक विजेता मीराबाई चानू ने सोमवार को महिलाओं के 48 किग्रा वर्ग में स्वर्ण पदक के साथ भारत के अभियान की शुरुआत की थी और अगले साल होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफिकेशन हासिल किया था।

गंभीर की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, हाई कोर्ट ने इस मामले में कार्यवाही पर रोक लगाने से किया इनकार

नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली उच्च न्यायालय पूर्व भारतीय क्रिकेटर और वर्तमान मुख्य कोच गौतम गंभीर के खिलाफ निचली अदालती कार्यवाही रोकने की याचिका से सहमत नहीं है। गंभीर, उनके फाउंडेशन और परिवार के सदस्यों पर अवैध रूप से कोविड-19 की दवाइयां वितरित करने के आरोप हैं। गंभीर के खिलाफ प्राथमिकी रद्द करने की याचिका दायर की गई थी। हालांकि न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने दृढ़ता से कहा कि अदालत इस अनुरोध पर विचार करेगी। न्यायाधीश ने कहा, अगर आपने एक साधारण अनुरोध किया होता, तो मैं उस पर विचार करती। आप मुझे बहुत सी बातें बताने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले (पार्टी का) नाम, उनकी साख, उनके द्वारा किए गए कार्य। आप नाम उछालने की कोशिश कर रहे हैं जैसे कि यह अदालत में काम करेगा। यह काम नहीं करता। अदालत की सुनवाई 8 सितंबर को होनी थी। यह भी कहा गया कि पूर्व सांसद और क्रिकेटर ने लॉकडाउन के दौरान ऑक्सीजन सिलेंडर और दवाइयां दान की थीं। हालांकि, उच्च न्यायालय अपने मूल रुख से पीछे नहीं हटा। उच्च न्यायालय ने कहा कि एक बार स्थगन आदेश लागू हो जाने पर सुनवाई तुरंत रुक जाती है, जांच रुक जाती है और पूरा मामला अंततः खारिज हो जाता है। यह शिकायत मूल रूप से औषधि नियंत्रण विभाग (डीसीडी) द्वारा गंभीर और उनके फाउंडेशन गौतम गंभीर फाउंडेशन और सीईओ अपराजिता सिंह के खिलाफ दर्ज की गई थी। उनकी मां (सीमा गंभीर) और पत्नी (नताशा गंभीर) को भी औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के उल्लंघनकर्ताओं के रूप में नामित किया गया है।

जॉन मूनी 6 साल बाद अफगानिस्तान क्रिकेट टीम में वापसी, एशिया कप से पहले मिली बड़ी जिम्मेदारी

नई दिल्ली, एजेंसी। आयरलैंड के पूर्व अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी जॉन मूनी छह साल के अंतराल के बाद अफगानिस्तान की राष्ट्रीय टीम में वापसी कर रहे हैं। बुधवार को अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने घोषणा की कि मूनी को उनकी राष्ट्रीय टीम का नया फील्डिंग कोच नियुक्त किया गया है। मूनी ने 2018 से 2019 तक अफगानिस्तान के साथ काम किया था, को शेन मैकडरमॉट के जाने के बाद यह पद खाली होने पर नियुक्त किया गया था। मैकडरमॉट वर्तमान में पाकिस्तान की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के फील्डिंग कोच के रूप में मार्गदर्शन कर रहे हैं। मूनी ने 91 अंतरराष्ट्रीय मैचों में आयरलैंड का प्रतिनिधित्व किया है, जिसमें 2007, 2011 और 2015 के तीन आईसीसी क्रिकेट विश्व कप और दो आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप शामिल हैं। उनके पास इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड से लेवल 3, 2 और 1 कोचिंग सर्टिफिकेट हैं। अफगानिस्तान के साथ काम करने के अलावा मूनी ने 2019 में वेस्टइंडीज के साथ और इस साल जनवरी से आयरलैंड की महिला टीम के साथ भी काम किया है। ACB ने ऑस्ट्रेलिया के निर्मलन थानाबालासिंगम को अपना नया फिजियोथेरेपिस्ट भी नियुक्त किया है। थानाबालासिंगम फिजियोथेरेपी और खेल विज्ञान में एक मजबूत शैक्षिक और व्यावसायिक पृष्ठभूमि लेकर आए हैं। उन्होंने 2010 में फिजियोथेरेपी में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की, और 2008 में सिडनी विश्वविद्यालय से व्यायाम और खेल विज्ञान में अनुप्रयुक्त विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। वह ऑस्ट्रेलिया के फिजियोथेरेपी बोर्ड में एक पंजीकृत चिकित्सक और ऑस्ट्रेलियाई फिजियोथेरेपी एसोसिएशन के एक सक्रिय सदस्य हैं। अफगानिस्तान वर्तमान में अबु धाबी में एक प्रशिक्षण और तैयारी शिविर में भाग ले रहा है, जहां वे त्रिकोणीय टी20 श्रृंखला की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान और मेजबान संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं, साथ ही पुरुष टी20 एशिया कप 2025 भी शामिल है।

कैरेबियन लीग में एक बॉल पर बने 22 रन, नो, वाइड, फिर लगातार 2 नो बॉल पर 2 सिक्स; अगली बॉल पर भी सिक्स

नई दिल्ली, एजेंसी। कैरेबियन प्रीमियर लीग में सोमवार रात एक बॉल पर 22 रन बने। मामला सेंट लूसिया ग्राउंड पर गयाना अमेजन वॉरियर्स और सेंट लूसिया किंग्स के बीच खेले गए मैच का है। टॉस जीतकर गयाना अमेजन वॉरियर्स पहले बैटिंग कर रही थी। रोमारियो शेफर्ड और इफ्तिखार अहमद क्रीज पर थे। 15वें ओवर की तीसरी गेंद पर 22 रन बने। ओशाने थॉमस ने ओवर की तीसरी गेंद नो बॉल डाली। इस पर बल्लेबाज और कोई रन नहीं बना सका। उन्होंने अगली गेंद वाइड डाली। फिर अगली दो गेंदें नो बॉल डाली। इन दोनों गेंदों पर बल्लेबाज शेफर्ड ने दो छक्के जड़ दिए। थॉमस ने अगली गेंद सही डाली। इस पर भी शेफर्ड ने छक्का जड़ दिया। इस तरह तीसरी गेंद पर कुल 22 रन बन गए। इसकी डिटेल्स अगले ग्राफिक्स में देख सकते हैं।

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के बाद अश्विन ने आईपीएल से भी संन्यास लिया

नई दिल्ली, एजेंसी। दिग्गज क्रिकेटर आर अश्विन ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के बाद आईपीएल से भी संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। अश्विन ने सोशल मीडिया के माध्यम से आईपीएल को अलविदा कहने की सूचना दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अश्विन ने लिखा, खास दिन और इसलिए एक खास शुरुआत। कहते हैं हर अंत की एक नई शुरुआत होती है। एक आईपीएल क्रिकेटर के रूप में मेरा समय आज समाप्त हो रहा है। लेकिन, विभिन्न लीगों में खेलने की संभावनाएं आज से शुरू हो रही हैं। इतने सालों की शानदार यादों और रिश्तों के लिए सभी फ्रेंचाइजी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। आईपीएल और बीसीसीआई का विशेष तौर पर शुक्रिया।

आगे जो भी है उसका आनंद लेने और उसका पूरा लाभ उठाने के लिए उत्सुक हूं। आईपीएल 2025 में अश्विन सीएसके का हिस्सा थे। टीम का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा था। ऐसे में अगले सीजन में टीम बड़े बदलावों के साथ उतर सकती हैं। अश्विन के सोशल मीडिया पोस्ट से यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि वह बेशक आईपीएल में खेलते हुए नहीं दिखेंगे, लेकिन दूसरी क्रिकेट लीग में खेलते हुए वह दिख सकते हैं। संभवत~ वह देश के बाहर खेली जाने वाली टी20 लीग में खेलते दिख सकते हैं। गौरतलब है कि बीसीसीआई भारत के अंतरराष्ट्रीय या घरेलू क्रिकेट से जुड़े किसी भी मौजूदा खिलाड़ी को विदेशी टी20 लीग में खेलने की छूट नहीं देता है। हालांकि, अब अश्विन संन्यास के बाद इन लीग में खेल सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की तरह अश्विन का आईपीएल करियर भी शानदार रहा है। 2008 से 2025 के बीच वह चेन्नई सुपर किंग्स, राइजिंग पुणे सुपर जाइंट्स, पंजाब किंग्स, दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स का हिस्सा रहे हैं। पंजाब किंग्स के वह कप्तान भी रहे हैं। 220 आईपीएल मैचों की 98 पारियों में 833 रन बनाने वाले अश्विन ने 187 विकेट लिए हैं। आईपीएल इतिहास के वह पांचवें सफलतम गेंदबाज हैं। अश्विन ने दिसंबर 2024 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहा था। आर अश्विन का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट बेहद यादगार रहा है। उनका नाम विश्व के श्रेष्ठतम ऑफ स्पिनर्स में शुमार किया जाता है। 2010 से 2024 के बीच 106 टेस्ट में 537 विकेट, 116 वनडे में 156 विकेट और 65 टी20 में 72 विकेट उनके नाम दर्ज हैं। टेस्ट क्रिकेट में अश्विन एक बल्लेबाज के रूप में भी सफल रहे हैं। 6 शतक और 14 अर्धशतक की मदद से उन्होंने 3,503 रन बनाए हैं।

FIDE World Cup: 23 साल बाद भारत में होगा फिडे विश्व कप का आयोजन

नई दिल्ली, एजेंसी। इस टूर्नामेंट में विश्व चैंपियन डी गुकेश, मैग्नस कार्लसन, फाबियानो करुआना और आर प्रज्ञानानंदा सहित 206 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि दो दशक से अधिक समय के बाद प्रतिष्ठित फिडे विश्व कप 2025 की मेजबानी करना भारत के लिए प्रसन्नता की बात है। पीएम मोदी ने कहा कि शतरंज युवाओं के बीच लोकप्रियता हासिल कर रहा है।

उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस टूर्नामेंट में रोमांचक मैच देखने को मिलेंगे और दुनिया भर के शीर्ष खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा, प्रतिष्ठित फिडे विश्व कप 2025 की मेजबानी करना भारत के लिए प्रसन्नता की बात है और वह भी दो दशक से अधिक समय के बाद। फिडे शतरंज विश्व कप का आयोजन गोवा में 30 अक्तूबर से 27 नवंबर तक किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में अगले साल के कैंडिडेट टूर्नामेंट के लिए तीन स्थान और 20 लाख डॉलर की इनामी राशि दांव पर लगी होगी। इस टूर्नामेंट में विश्व चैंपियन डी गुकेश, मैग्नस कार्लसन, फाबियानो करुआना और आर प्रज्ञानानंदा सहित 206 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। भारत के लिए यह बड़ा अवसर है क्योंकि 23 साल बाद पहली बार देश में इस टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा। पिछली बार 2002 में हैदराबाद में भारत ने इस प्रतियोगिता की मेजबानी की थी और तब विश्वनाथन आनंद ने खिताब जीता था।

भारत ने पिछले कुछ वर्षों में शतरंज में काफी तरक्की की है। यह टूर्नामेंट आठ दौर में दो बाजियों के नॉकआउट प्रारूप में खेला जाएगा। दो क्लासिकल बाजियां होंगी जिनमें बराबरी पर रहने पर रैपिड और ब्लिट्ज प्लेऑफ होंगे।

Football: भारतीय फुटबॉल महासंघ पर फिर मंडराया प्रतिबंध का खतरा

नई दिल्ली, एजेंसी। यह पहली बार नहीं है जब भारतीय फुटबॉल को इस तरह की शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है। अगस्त 2022 में फीफा ने भारत को 'तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप' के आरोप में निलंबित कर दिया था। भारतीय फुटबॉल पर अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध का खतरा मंडरा रहा है क्योंकि वैश्विक संचालन संस्था फीफा और एशियाई फुटबॉल परिसंघ (एएफसी) ने संकटग्रस्त अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआईएफएफ) को सख्त चेतावनी दी है कि उसे 30 अक्तूबर तक नया संविधान अपनाना और उसकी पुष्टि करनी होगी या फिर निलंबन का जोखिम उठाना पड़ेगा। एआईएफएफ अध्यक्ष कल्याण चौबे को मंगलवार को लिखे दो पन्नों के कड़े पत्र में दोनों अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं ने 2017 से उच्चतम न्यायालय में मामला लंबित होने के बावजूद महासंघ द्वारा अपने संविधान

को अंतिम रूप देने में विफलता पर 'गहरी चिंता' व्यक्त की। शीर्ष अदालत गुरुवार को इस मामले की सुनवाई करेगी।

निलंबन का क्या मतलब?

निलंबन का मतलब होगा कि राष्ट्रीय टीमों और क्लबों को सभी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा और साथ ही अहमदाबाद में 2036 के ओलंपिक खेलों के लिए भारत की महत्वाकांक्षी बोली भी अनिश्चितता में पड़ जाएगी। फीफा और एएफसी ने चौबे के नेतृत्व वाले एआईएफएफ को संशोधित संविधान को मंजूरी देने के लिए उच्चतम न्यायालय से एक 'निश्चित आदेश' प्राप्त करने, इसे फीफा और एएफसी के अनिवार्य नियमों के अनुरूप बनाने और 30 अक्तूबर की समय-सीमा से पहले अगली आम सभा की बैठक में इसकी पुष्टि करने का निर्देश दिया है।

पत्र में कहा गया है, इस कार्यक्रम का पालन नहीं करने पर हमारे पास इस मामले को निर्णय लेने वाली फीफा की संबंधित संस्था के पास विचार और निर्णय के लिए भेजने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगाज जिसमें निलंबन की संभावना भी शामिल है। इस पत्र पर फीफा के मुख्य सदस्य संघ अधिकारी एल्खान मामादोव और एएफसी के उप महासचिव (सदस्य संघ) वाहिद कर्दानी ने संयुक्त रूप से हस्ताक्षर किए हैं।

अनीष भानवाला के हाथों से छूटा गोल्ड, एशियाई चैंपियनशिप में जीता रजत पदक

शिमकेंट (कजाखस्तान), एजेंसी। भारतीय निशानेबाज अनीष भानवाला ने बुधवार को यहां एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में पुरुष 25 मीटर रेपिड फायर पिस्टल स्पर्धा का रजत पदक जीता। 22 साल के अनीष स्वर्ण पदक की दौड़ में सिर्फ एक अंक से चूक गए। उन्होंने 35 अंक जुटाए जो स्वर्ण पदक विजेता चीन के शु लियानबोफान से एक अंक कम रहा। कांस्य पदक कोरिया के ली जेइकयून ने जीता। अनीष शुरुआती चार सीरीज के बाद एक अंक से आगे चल रहे थे लेकिन इसके बाद पिछड़ गए। मंगलवार को ओलंपियन सिफत कौर सामरा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए महिला 50 मीटर राइफल थ्री पोजिशंस में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने के अलावा देश को टीम खिताब भी दिलाया। भारत ने प्रतियोगिता में अब तक 72 पदक जीते हैं। प्रतियोगिता में जूनियर स्पर्धाएं भी हो रही हैं। जूनियर निशानेबाजों के शानदार प्रदर्शन की बदौलत भारत ने अब तक 39 स्वर्ण पदक हासिल किए हैं।

यूएस ओपनः

वीनस विलियम्स और लेयला फर्नांडीज के बीच होगा महिला युगल मैच

न्यूयॉर्क, एजेंसी। यूएस ओपन महिला एकल में पहले राउंड से ही बाहर हुई वीनस विलियम्स का अभियान अभी समाप्त नहीं हुआ है। वीनस महिला युगल में लेयला फर्नांडीज के साथ खेलती हुई दिखेंगी। उन्हें वाइल्ड-कार्ड एंट्री दी गई है।

वीनस विलियम्स और लेयला फर्नांडीज का मुकाबला छठी वरीयता प्राप्त यूक्रेन की ल्यूडमिला किचेनोक और ऑस्ट्रेलिया की एलेन पेरेज की जोड़ी से होगा। 22 वर्षीय फर्नांडीज को न्यूयॉर्क में महिला एकल में 31वीं वरीयता दी गई है और उन्होंने पहले दौर में हमवतन रेबेका मैरिनो को 6-2, 6-1 से हराया। वह 2021 में एकल फाइनल में पहुंचीं, जहां

वह ब्रिटेन की एम्मा राडुकानू से उपविजेता रहीं। 45 साल की वीनस 2 साल में पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में भाग ले रही हैं। वीनस विलियम्स महिला युगल की सफलतम खिलाड़ियों में से एक हैं। अपनी बहन सेरेना विलियम्स के साथ उन्होंने 14 ग्रैंड स्लैम महिला युगल खिताब जीते हैं। आखिरी बार 2016 में उन्होंने विंबलडन जीता था। महिला युगल में वह आखिरी बार 2022 में सेरेना विलियम्स के साथ यूएस ओपन में दिखी थी। वह सेरेना का विदाई टूर्नामेंट था। 2025 यूएस ओपन में, विलियम्स पहले ही महिला एकल और मिश्रित युगल (रीली ओपेल्का के साथ) में भाग ले चुकी हैं। सोमवार रात, उन्होंने आर्थर ऐश स्टेडियम में एक रोमांचक दूसरे सेट में जीत हासिल की, लेकिन अंततः 11वीं वरीयता प्राप्त कैरोलिना मुचोवा से 6-3, 2-6, 6-1 से हार गईं। 1981 में रेनी रिचर्ड्स के बाद विलियम्स यहां महिला एकल में प्रतिस्पर्धा करने वाली सबसे उम्रदराज खिलाड़ी थीं और ओपन एरा की तीसरी सबसे उम्रदराज खिलाड़ी थीं।

विलियम्स और फर्नांडीज महिला युगल ड्रॉ में सात वाइल्ड-कार्ड टीमों में शामिल हैं, जिनमें हैली बैप्टिस्ट और व्हिटनी ओसुइग्वे, रीज ब्रैंटमेयर और एलानिस हैमिल्टन, कारमेन कॉर्ली और इवाना कॉर्ली, क्रिस्टीना पेनिकोवा और थिया फ्रोडिन, क्लर्वी न्गोउए और इवा जोविक, और जूलियट पारेजा और आकाश उरहोबो शामिल हैं। 2025 यूएस ओपन महिला युगल प्रतियोगिता गुरुवार को यूएसटीए बिली जीन किंग नेशनल टेनिस सेंटर में शुरू होगी।